

एयर इंडिया का पुनः “राष्ट्रीयकरण” (नैशनलाइज़ेशन) करने की माँग उठने लगी है

रद्द उड़ानें, उड़ान भरने में बेवजह देरी आदि कारणों से यह छवि बन रही है कि एयर इंडिया में अब शीर्ष स्तर पर नागरिक उड्डयन (सिविल एविएशन) के पर्याप्त अनुभव की कमी है

—सुकुमार साह—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 03 अगस्त। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी द्वारा टाटा समूह से एयर इंडिया को वापस लेने की सरकार से की गई मांग ने एक बार फिर उस बहस को ज़िंदा कर दिया है, जिसके बारे में कई लोगों का मानना था कि जनवरी 2022 में एयरलाइन के निजीकरण के साथ ही यह मामला सुलझ गया था। टाटा के नेतृत्व वाली एयर इंडिया के “प्रबंधन में गड़बड़ी” बताते हुए, तिवारी ने समूह पर राष्ट्रीय संपत्ति को कुप्रबंधन की मिसाल बनाने का आरोप लगाया, जिसमें उड़ान रद्द हो रही हैं समय पर उड़ानें नहीं मिल रही और विमानन क्षेत्र की समझ की कमी दिखाई दे रही है। तिवारी की निराशा पूरी तरह निराधार नहीं है। सोशल मीडिया पर यात्रियों की शिकायतें भरी पड़ी हैं, अनियमित समय-सारणी, खराब ग्राहक सेवा और व्यवस्थागत गड़बड़ियाँ। समूह द्वारा आधुनिक, और

- पर, क्या पुनः नैशनलाइज़ेशन करना इस समस्या का सही निदान है। क्योंकि एयर इंडिया को टाटा समूह को सौंपना एक “इमोशनल” निर्णय नहीं था, बल्कि आर्थिक विवशता दी। एयर इंडिया 60 हजार करोड़ रूपए का घाटा दे चुकी थी तथा सरकार के अनुदान के कारण घिसट रही थी। आशा की थी कि प्राइवेट हाथों में मैनेजमेंट जाने के बाद, यह घाटा रूकेगा तथा धीरे-धीरे एयर इंडिया चुस्त होकर अपने पैरों पर खड़ी हो जायेगी।
- टाटा संस ने चुस्त बनाने की दिशा में कदम भी उठाये तथा सिविल एविएशन इंडस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर दिया नये हवाई जहाजों के लिए। स्टाफ के प्रशिक्षण के नये कोर्स शुरु किये गये तथा एयर इंडिया ब्राण्ड की विश्वसनीयता पुनः स्थापित करने की कोशिश की गई। पर, यह काम वर्षों चलने के बाद रिजल्ट दिखाता है। अतः एक प्रतिक्रिया यह भी है कि अब पुनः नैशनलाइज़ेशन की बात करना न्यायोचित नहीं है।

यात्रियों के अनुकूल एयर इंडिया का जो वादा किया गया था, वह अब तक पूरी तरह हकीकत नहीं बन पाया है। लेकिन

क्या इन शुरुआती समस्याओं की वजह से एक ऐतिहासिक सुधार को वापस लिया जाना चाहिए? क्या सरकार को

उस एयरलाइन को फिर से अपने हाथ में लेना चाहिए, जिसे वह सालों तक सक्बिडी देकर भी चला नहीं पाई थी? पहले यह समझना जरूरी है कि एयर इंडिया का निजीकरण कोई आइडियोलॉजिकल फैसला नहीं था, बल्कि एक वित्तीय मजबूरी थी। यह एयरलाइन सरकार के लिए एक आर्थिक बोझ बन चुकी थी, 60,000 करोड़ से अधिक का नुकसान था, और सरकारी मदद से ही चल रही थी। करदाताओं का पैसा इस अनुत्पादक संस्था को बचाने में खर्च हो रहा था, जबकि वही पैसा स्वास्थ्य सेवा या बुनियादी ढाँचे में लग सकता था।

यह तो कहना पड़ेगा कि टाटा संस ने एक बहुत ही जटिल और संकटग्रस्त एयरलाइन संभाली है। चार एयरलाइनों (एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस, विस्तारा और एयरएशिया इंडिया) का एकीकरण कोई आसान काम नहीं है। टाटा ने विमानन इतिहास का सबसे बड़ा (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

उम्र कैद की सजा के खिलाफ रेवन्ना हाई कोर्ट पहुँचे

बेंगलु, 03 अगस्त। यौन शोषण के एक मामले में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु स्थित सांसदों/विधायकों की विशेष अदालत (एमपी/एमएलए कोर्ट) की ओर से आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद जनता दल (सेक्युलर) के नेता प्रज्वल रेवन्ना को बेंगलुरु के परम्पना अग्रहारा केंद्रीय कारागार में कैदी नंबर दिया गया। इस बात की जानकारी रविवार (3 अगस्त, 2025) को जेल अधिकारियों ने दी।

प्रज्वल ने कथित तौर पर

- यौन शोषण के मामले में सांसद विधायकों की विशेष अदालत ने शेष जीवन तक कारावास की सजा सुनाई थी।

कर्मचारियों को सूचित किया है कि उसने अपनी सजा को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। पूर्व सांसद फिलहाल उच्च सुरक्षा वाली कोठरी में बंद है और उसे कड़ी सुरक्षा दी जा रही है। प्रज्वल को शनिवार (2 अगस्त) को शेष जीवन तक कारावास में रहने की सजा सुनाई गई और कुल 11.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने निर्देश दिया कि 11.25 लाख रुपये रेवन्ना के परिवार की घरेलू सहायिका व पीड़िता को दिए जाएं।

‘साढ़े छः लाख बिहारी श्रमिकों को तमिलनाडु का मतदाता बनाना अवैध’

चिदंबरम ने इसे तमिलनाडु के मतदाताओं के मनपसंद सरकार चुनने के अधिकार में हस्तक्षेप बताया

चेन्नई, 03 अगस्त। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने रविवार को कहा कि तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी श्रमिकों को भी मतदान का अधिकार देने का चुनाव आयोग का फैसला चिंताजनक और अवैध है। उन्होंने यह भी कहा कि यह कदम तमिलनाडु के मतदाताओं के मनपसंद सरकार चुनने के अधिकार में घोर हस्तक्षेप होने के साथ-साथ प्रवासी श्रमिकों का भी “अपमान” है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में चिदंबरम ने कहा, “जहाँ बिहार में 65 लाख मतदाताओं के मताधिकार से वंचित होने का खतरा मंडरा रहा है, वहीं तमिलनाडु में 6.5 लाख लोगों को मतदाता के रूप में जोड़ने की खबरें चिंताजनक और स्पष्ट रूप से अवैध हैं। उन्हें “स्थायी प्रवासी” कहना प्रवासी श्रमिकों का अपमान है और तमिलनाडु के मतदाताओं के अपनी नहीं लौटते, जैसा कि वे आमतौर पर करते हैं? क्या प्रवासी श्रमिक छठ पूजा के त्योहार के समय बिहार नहीं लौटते?

- चिदंबरम ने कहा कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया रोजाना अजीब होती जा रही है। अगर प्रवासी मजदूर के परिवार का बिहार में स्थायी घर है तो उसे तमिलनाडु में “स्थायी प्रवासी” कैसे माना जा सकता है?”

प्रवासी श्रमिक जैसे छठ पूजा में वापस घर जाते हैं वैसे ही वे चुनावों में मतदान के लिए गृह राज्य क्यों नहीं जा सकते। उन्होंने कहा, "प्रवासी श्रमिक विधानसभा चुनाव में मतदान करने के लिए बिहार (या अपने गृह राज्य) क्यों नहीं लौटते, जैसा कि वे आमतौर पर करते हैं? क्या प्रवासी श्रमिक छठ पूजा के त्योहार के समय बिहार नहीं लौटते?

जब प्रवासी श्रमिक का बिहार (या दूसरे राज्य) में घर है तो उन्हें तमिलनाडु की मतदाता सूची में कैसे जोड़ा जा सकता है?" चिदंबरम ने कहा कि चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया रोजाना ही और भी ज्यादा अजीब होती जा रही है। अगर प्रवासी मजदूर के परिवार का बिहार में स्थायी घर है और वह बिहार में रहता है, तो उसे तमिलनाडु में “स्थायी प्रवासी” कैसे माना जा सकता है?" उन्होंने पोस्ट में लिखा, "चुनाव आयोग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है और राज्यों के चुनावी चरित्र और पैटर्न को बदलने की कोशिश कर रहा है। शक्तियों के इस दुरुपयोग का राजनीतिक और कानूनी विरोध करना चाहिए। विदित हो कि इससे पहले ड्रिविड मुनेत्र कथमग (द्रमुक) और उसके सहयोगी दलों ने राज्य में प्रवासी मजदूरों को वोट देने का अधिकार देने के चुनाव (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सितंबर से रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा बंद होगी

नई दिल्ली, 03 अगस्त। भारतीय डाक विभाग ने बड़ा ऐलान किया है, जिसमें बताया गया है कि 1 सितंबर से रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा को अब स्पीड पोस्ट के साथ ही मिला दिया जाएगा। यानी अब ग्राहकों को पार्सल भेजने के लिए सिर्फ स्पीड पोस्ट की ही सुविधा मिलेगी। डाक विभाग ने बताया है कि इस फैसले के बाद पोस्ट सर्विस तेज और आधुनिक बनेगी।

- डाक विभाग, स्पीड पोस्ट सर्विस को तेज और आधुनिक बनायेगा।

सर्विस की सुविधा साल1854 में शुरू की गई थी। इसके जरिए ग्राहक जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ कीमती सामानों को भेजा करते थे। हालांकि अब 1 सितंबर से रजिस्टर्ड पोस्टसेबल नहीं मिलेगा। रजिस्टर्ड पोस्ट सर्विस में ग्रूफ ऑफ डिलीवरी और रिसीवर के सिग्नेचर की जरूरत होती थी, जो अब ये स्पीड पोस्ट में मिलेगी।

आधिकारिक डाक डेटा 2011– (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सरयू नहर में बोलेरो डूबी, 11 की मौत

मृतकों में गोंडा के सीहा गाँव के 3 भाईयों के परिवार के 9 सदस्य व दो पड़ोसी हैं

गोंडा, 03 अगस्त। यूपी के गोंडा में रविवार सुबह 10 बजे तेज रफ्तार बोलेरो बेकाबू होकर सरयू नहर में गिर गई। हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। इनमें 3 भाइयों के परिवार के 9 लोग थे, जबकि 2 लोग पड़ोसी परिवार के थे। छोटे भाई का पूरा परिवार खत्म हो गया। ड्राइवर सहित 4 लोग बच गए। अभी 10 साल की बच्ची लापता है। एसडीआरएफ टीम उसकी तलाश में जुटी है।

बोलेरो सवार 16 लोग जल चढ़

ने पृथ्वीनाथ मंदिर जा रहे थे। सभी गोंडा के मोतीगंज थाना के सीहा गाँव के रहने वाले थे। हादसा इतना भयावह था कि गाड़ी नहर में गिरने के बाद एक भी शख्स बाहर नहीं निकल पाया। बारिश के कारण नहर में लबालब पानी भरा है। नहर में गिरते ही गाड़ी पूरी तरह से डूब गई। उसके गेट लॉक हो गए। अंदर बैठे

लोग छटपटाते रहे।

जानकारी के अनुसार, गाड़ी नहर के किनारे बनी सड़क से निकल रही थी। नहर क्रॉस करके जाना था। पुलिस के पास अचानक ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, तेज स्पीड और बारिश की वजह से गाड़ी बेकाबू होकर नहर में गिरने लगी। इस पर ड्राइवर गेट खोलकर कूद गया। आगे की सीट में बैठे 2 लोग भी बाहर आ गए। बच्ची पिंकी बीच में खड़ी थी। ड्टके से वह भी ड्राइवर साइड के गेट से बाहर आ गई। इसके बाद बोलेरो नहर में गिर गई।

जहां हादसा हुआ, वहां आसपास ग्रामीण मौजूद थे। बोलेरो नहर में गिरती देख वो लोग बचाने के लिए पानी में कूद गए, लेकिन गेट नहीं खोल पाए। रस्सी बांधकर बोलेरो को किनारे तक लाए, तब जाकर गाड़ी का कुछ हिस्सा बाहर (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ग्रेनाइट खदान में बोल्ट्जर गिरने से 6 मजदूरों की मौत

बापतला, 03 अगस्त। आंध्रप्रदेश में बापतला जिले के बल्लीकुरवा गाँव में एक ग्रेनाइट खदान में रविवार को एक भारी शिलाखंड (बोल्ट्जर) गिरने से छह मजदूरों की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हो गये।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि मजदूरों का एक समूह सत्य कृष्णा ग्रेनाइट खदान में काम कर रहा था, तभी एक पहाड़ी से विशाल पत्थर लुढ़ककर उन पर गिर गया जिसमें छह मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गयी। अब तक चार शव बाहर निकाले जा चुके हैं और दो

- आंध्र प्रदेश में हुई दुर्घटना में चार अन्य मजदूरों की हालत नाजुक है।

को निकालने के प्रयास जारी है। जिस समय यह हादसा हुआ, तब ग्रेनाइट खदान में 16 मजदूर काम कर रहे थे।

इस हादसे में घायल अन्य मजदूरों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ चार मजदूरों की हालत नाजुक बताई जा रही है। प्रारंभिक जाँच के अनुसार, हादसे में मारे जाने वाले मजदूर ओडिशा के थे। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

गडकरी के घर को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार

नागपुर, 03 अगस्त। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नागपुर स्थित घर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पुलिस कंट्रोल रूम को ये धमकी भरा कॉल आया है। इस कॉल के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। कुछ ही देर में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

मिली जानकारी के अनुसार,रविवार सुबह 8:46 बजे

- रविवार की सुबह पुलिस कंट्रोल रूम में बम से उड़ाने की धमकी का फोन आया था।
- नागपुर पुलिस ने गडकरी के घर पर डोंग स्क्वाड के साथ सर्च ऑपरेशन चलाया। कुछ घंटों में ही धमकी देने वाला गिरफ्तार हो गया। वह एक देशी शराब की दुकान पर काम करता है।

पुलिस कंट्रोल के 112 नंबर पर गडकरी के घर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी का कॉल आने के बाद पुलिस ने स्थानीय पुलिस थाने को मामले की जानकारी दी है। कंट्रोल रूम को कॉल आने के बाद प्रताप नगर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव से दो वोटर आईडी कार्ड पर जवाब मांगा

आयोग ने तेजस्वी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाये वोटर कार्ड की मूल प्रति मांगी

पटना, 03 अगस्त। बिहार विधानसभा चुनावों की तैयारियों में सभी पार्टियां जुटी हुई हैं। इस बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ ती हुई दिख रही है। चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस जारी किया है और 2 वोटर आई कार्ड के संबंध में जवाब मांगा है। चुनाव आयोग के अनुसार, तेजस्वी यादव की प्रेस वार्ता के दौरान दिखाए गए इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड (ई.पी.आई.सी.) संख्या आरएबी 2916120 की जांच की जाएगी। आयोग ने तेजस्वी यादव से इसकी मूल प्रति मांगी है, जिसके लिए नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग की प्राथमिक जांच के अनुसार, तेजस्वी को ई.पी.आई.सी. कार्ड का

विवरण (कार्ड की मूल प्रति सहित) आयोग को उपलब्ध कराने को कहा गया है ताकि इसकी गहन जांच की जा सके। दरअसल तेजस्वी यादव ने दावा किया था कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है। तेजस्वी ने शनिवार को पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उन्होंने अपने ई.पी.आई.सी. नंबर (आरएबी 2916120) को चुनाव आयोग की वेबसाइट पर सर्च किया, लेकिन नो रिकॉर्ड

- आयोग का कहना है कि जो कार्ड तेजस्वी ने दिखाया वह 10 साल से रिकॉर्ड में नहीं है तथा गत दो चुनाव तेजस्वी यादव ने जिस वोटर आईडी पर लड़े, वह दूसरा है।

तेजस्वी का नाम वोटर लिस्ट में मतदान केंद्र संख्या 204, क्रमांक 416 पर दर्ज है। उनका वैध ई.पी.आई.सी. नंबर आरएबी 0456228 है। चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया था कि तेजस्वी ने पीसी के दौरान जो ई.पी.आई.सी. नंबर आरएबी 2916120 दिखाया, वो पिछले

10 साल में कहीं रिकॉर्ड में नहीं है। जबकि तेजस्वी ने जिस ई.पी.आई.सी. नंबर आरएबी 0456228 के आधार पर 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव लड़े, वो आधिकारिक रिकॉर्ड में मौजूद है। बिहार एनडीए के घटक दलों के प्रवक्ताओं ने रविवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और राजद के नेता तेजस्वी यादव पर जमकर सियासी हमला बोला। एनडीए प्रवक्ताओं ने दो ई.पी.आई.सी. नंबर पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह आया कहां से? कोई भी व्यक्ति दो मतदाता पहचान (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सरकार ने 35 जरूरी दवाओं की कीमत घटाई

नई दिल्ली, 03 अगस्त। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब कई जरूरी दवाएं पहले से सस्ती मिलेंगी। सरकार ने 35 जरूरी दवाओं की कीमत घटा दी है, जिससे दिल, डायबिटीज, मानसिक रोग और इन्फेक्शन जैसी बीमारियों के मरीजों को सीधी राहत मिलेगी। ये फैसला रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने एनपीपीए की सिफारिश पर लिया है। इसके तहत जिन दवाओं की कीमतें कम की गई हैं, वह लंबे समय से चल रही बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होती हैं। प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के अंतर्गत आने वाले प्रमुख

- नोटिफाइड कीमतों की पालना नहीं करने पर दंडात्मक प्रावधान लागू होंगे।

फॉर्मूले में एसक्लोफेनाक, पैरासिटामोल और ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन, एमोक्सिसिल्लिन और पोटेशियम क्लैबुलनेट के फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन, एटोरवास्टेटिन कॉम्बिनेशन और एम्पैग्लिफ्लोजिन, सिटार्ग्लिटिन और मेटफॉर्मिन जैसे नए ओरल एंटीडायबिटिक कॉम्बिनेशन शामिल हैं।

नोटिफाइड कीमतों का पालन न करने पर डीपीसीओ, 2013 और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दंडात्मक प्रावधान लागू हो सकते हैं, जिसमें ब्याज सहित (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विचार बिन्दु

मस्तिष्क इन्द्रियों की अपेक्षा महान है, शुद्ध बुद्धिमत्ता मस्तिष्क से महान है, आत्मा बुद्धि से महान है, और आत्मा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। –स्वामी शिवानंद

हमारे बच्चे और सोशल मीडिया

क्या आप जानते हैं कि हम भारतीय सोशल मीडिया का कितना प्रयोग करते हैं? शायद यह बात आपके लिए भी चौंकाने वाली हो कि पूरी दुनिया में सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा प्रयोग हम भारतीय ही करते हैं। हमारे यहां एक व्यक्ति औसतन 11 प्लेटफॉर्म पर सक्रिय रहता है और हर दिन लगभग 7.3 घण्टे स्क्रीन पर (मोबाइल या अन्य) व्यतीत करता है। समझा जा सकता है कि जब बड़े इतना समय स्क्रीन को देते हैं तो अपने बच्चों को इसका इस्तेमाल करने से शायद ही रोक पाते होंगे। वैसे भी कोरोना काल में तत्कालीन विवशताओं की वजह से शिक्षा के लिए मोबाइल का प्रयोग अपरिहार्य हो गया था। जो मां-बाप अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखना चाहते थे उन्हें भी आगे बढ़कर अपने बच्चों के हाथों में मोबाइल देना पड़ा था। और उसके बाद बहुत मुमकिन है कि उनमें से बहुत सारे लोग उस मोबाइल को वापस लेना भूल गए हों।

हम अपने चारों तरफ देखते हैं कि अधिकांश मां-बाप अपने बच्चों के प्रति अपने लाडल का प्रदर्शन करने के लिए औचित्य की बहुत सारी सीमाओं की अनदेखी कर जाते हैं। वे बच्चों को बिना रोक-टोक के फास्ट फूड का उपभोग करने देते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने का पात्र बनने उससे पहले वे उन्हें अपने वाहनों की चाबियां सौंप देते हैं और लाड-लाड में न केवल उन्हें मोबाइल का निर्बाध प्रयोग करने देते हैं, खुद आगे बढ़कर उन्हें मोबाइल खरीद कर भी दे देते हैं। अगर मां-बाप न दें या देने की स्थिति में न हों तो बच्चे खुद लड-झगड़कर हासिल कर लेते हैं। बहुत बार यह भी देखा गया है कि ये सारी गतिविधियां करते हुए मां-बाप लज्जित नहीं गर्वित होते हैं।

इन बहुत सारी बातों के बीच से आज हम चर्चा यह करना चाह रहे हैं कि क्या बच्चों को सोशल मीडिया का निर्बाध या सीमित उपयोग करने देना चाहिए? यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि हाल में ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने घोषणा की है कि सन 2025 की पहली दिसम्बर से वहां सोलह बरस से कम उम्र के बच्चे यूट्यूब का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। इस निषेध का उल्लंघन करने पर यूट्यूब की 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर अर्थात लगभग 282 करोड़ रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। असल में वहां की सरकार ने एक अध्ययन करवाया था जिससे ज्ञात हुआ कि ऑस्ट्रेलिया में 10 से 12 बरस की आयु के 68 प्रतिशत बच्चे नियमित रूप से यूट्यूब देखते हैं और यूट्यूब का एल्गोरिदम कुछ इस तरह का है कि वह बच्चों को खतरनाक स्टंट, हिंसा, डरावने दृश्यों और अश्लीलता भरे वीडियो या शॉर्ट्स बार-बार दिखाता है। इस कारण इन बच्चों में बहुत तेजी से डोपाइमाइन साइकल बनने लगा है और इसका कुप्रभाव उनकी नींद, पढ़ाई और मानसिकता पर पड़ रहा है। यहीं यह भी जान लें कि ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के लिए टिकटोंक, इंस्टाग्राम, स्नैपैट और फ़ेसबुक का प्रयोग पहले से वर्जित है।

इसी ज्ञान में यह भी जान लिया जाए कि ऑस्ट्रेलिया के अलावा भी दुनिया के बहुत सारे देशों में बच्चों के सोशल मीडिया प्रयोग पर बंदिशें लागू हैं। फ्रांस में 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे वगैर माता-पिता की अनुमति के सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और जैसे इतना ही पर्याप्त न हो वहां तो 15 वर्ष की उम्र तक के बच्चों द्वारा मोबाइल के उपभोग को पूरी तरह बंद करने के मामले में भी एक दायल चल रही है। फ्रांस की ही तरह जर्मनी में भी 13 से 16 वर्ष तक की आयु के बच्चे वगैर मां-बाप की अनुमति के सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। बेल्जियम में यह प्रतिबंध 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रभावी है।

हमारे यहां अगर कानून बन भी जाएगा तो

यह निश्चित मानिए कि उसके पालन से

ज़्यादा उसका उल्लंघन होगा, और अंततः

वह कानून मज़ाक बन कर रह जाएगा।

अधिकांश मां-बाप में इस समझ का अभाव

है कि मोबाइल और सोशल मीडिया का

अत्यधिक प्रयोग उनके बच्चों के मानसिक

स्वास्थ्य के लिए घातक है। उन्हें यह बात

समझाने का न तो किसी में धैर्य है, न

उत्साह और न इच्छा।

रोका गया था। यह बात अलग है कि वहां बाद में यह प्रतिबंध हटा लिया गया। संयुक्त राज्य अमरीका में चिल्ड्रन्स ऑनलाइन प्राइवसी प्रोटेक्शन एक्ट के अन्तर्गत 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की निजी जानकारी एकत्रित करना वर्जित है। और यूरोपीय संघ, फ्रांस और स्पेन जैसे देश 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया प्रयोग के लिए मां-बाप की सहमति अनिवार्य करने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं।

अब ज़रा एक नज़र अपने देश की स्थिति पर भी डाल लें। अप्रैल 2024 में हमारे सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर हुई थी जिसमें 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग को प्रतिबंधित करने की मांग की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने संसद का विचारणीय विषय बताते हुए इस याचिका को खारिज़ कर दिया। असल में अभी भारत में बच्चों के सोशल मीडिया उपभोग को प्रतिबंधित करने पर कोई गंभीर विचार नहीं हो रहा है। इसकी बजाय हम सामाजिक सहमति, अभिभावकों के विवेक और डेटा सुरक्षा पर भरोसा कर रहे हैं।

सोशल मीडिया और स्क्रीन के प्रयोग, प्रयोग के सीमा उल्लंघन और प्रयोग के खतरों से हम सभी वाकिफ़ हैं। बच्चों के हाथ में जब स्क्रीन होता है तो वे उस पर किस तरह का कंटेंट देखते हैं, इस बात पर बड़ों का बहुत कम नियंत्रण संभव होता है। भारत जैसे देश में जहां मां-बाप अपनी रोज़ी-रोटी की समस्याओं में बहुत बुरी तरह उलझे होते हैं, उनसे यह उम्मीद करना कि वे यह देखेंगे कि बच्चे मोबाइल या कंप्यूटर का उपयोग किस काम के लिए कर रहे हैं, उनके प्रति ज़्यादती ही होगा। स्कूलों की हो हालत है,खास तौर पर सरकारीस्कूलों की, वहां काम के बोझ से दबे (और कभी-कभी काम से बचने वाले भी) अध्यापकों से कोई उम्मीद की ही नहीं जा सकती। यह भी सही है कि आज मोबाइल हम सबके लिए इतना अपरिहार्य हो गया है कि उससे बच्चों को वंचित रखना व्यावहारिक नहीं रह गया है। मोबाइल तो उन्हें देना ही पड़ेगा। और जब आप उन्हें यह उपकरण सौंप देंगे तो फिर वे उसका कैसा उपयोग करेंगे, यह तय करना आपके लिए बहुत कठिन है।

और बात केवल बच्चों की नहीं है। यह भी देखा जाए कि बड़े भी मोबाइल के किस तरह एडिक्ट हो चुके हैं। इस बात की विस्तृत विवेचना अनावश्यक है। अब जो मां-बाप खुद मोबाइल से चिपके हुए हैं वे अपने बच्चों को इसका प्रयोग करने से कैसे रोकेंगे? बहुत बार तो हम देखते हैं कि मां-बाप इस बात पर गर्व करते हैं कि उनका शिशु मोबाइल के बगैर खाना तक नहीं खाता है या उनका बारह वर्ष का बेटा किस फर्पटे से स्कूटर दौड़ाता है। यह बताते हुए उनके चेहरे पर अपराध बोध नहीं गर्व झलकता है। बहुत सारे शिक्षक बताते हैं कि अगर वे बच्चों को फास्ट फूड का प्रयोग करने से रोकते हैं तो उनके मां बाप लड़ने के लिए आ जाते हैं।

ऐसे में भारत जैसे देश की स्थितियां अन्य देशों से बहुत अलग हैं। हमारे यहां अगर कानून बन भी जाएगा तो यह निश्चित मानिए कि उसके पालन से ज़्यादा उसका उल्लंघन होगा, और अंततः वह कानून मज़ाक बन कर रह जाएगा। अधिकांश मां-बाप में इस समझ का अभाव है कि मोबाइल और सोशल मीडिया का अत्यधिक प्रयोग उनके बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए घातक है। उन्हें यह बात समझाने का न तो किसी में धैर्य है, न उत्साह और न इच्छा। ऐसे में जो समझदार लोग हैं वे दुखी होते रहेंगे, और उनके बच्चे यह देखकर अपने मां-बाप पर कुढ़ते रहेंगे कि उनके अन्य दोस्तों के मां-बाप जिस काम के लिए अपने बच्चों को बिल्कुल भी नहीं रोक रहे हैं, उसी काम के लिए उनके मां-बाप उनसे रोज़ किंच-किंच क्यों करते हैं। ऐसे में बस यही संभावना बची रहती है कि जो मां-बाप इस बात को समझते हैं वे अपने बच्चों के सोशल मीडिया और स्क्रीन प्रयोग पर निगाह रखें और प्रयास करें कि बच्चे इनका सीमित प्रयोग करें।

–अतिथि संपादक,
डॉ. दुर्गाप्रसाद अग्रवाल
(शिक्षाविद और साहित्यकार)



बालमुकुंद आन्ना

राजस्थान के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में बीते 2022 के बाद से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं। छात्रों के साथ ही छात्र संगठन लगातार चुनाव की मांग करते आ रहे हैं। गहलोत सरकार ने 2023 में विधानसभा चुनाव के चलते चुनाव स्थगित किये थे। इसके बाद आई भाजपा सरकार ने भी चुनाव कराने की कोई घोषणा नहीं की है। दिल्ली विश्व विद्यालय छात्र संघ के चुनावों के बाद राजस्थान में भी छात्र संघों के चुनावों की मांग जोर शोर से उठ रही है। राजस्थान में छात्रसंघ चुनावों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। वहीं छात्र संघों के चुनाव कराने को लेकर छात्र नेताओं

ने आंदोलन का बिगुल बजा दिया है। छात्रों ने सरकार द्वारा छात्र संघों के चुनाव नहीं कराने के फैसले के विरोध में उठा आंदोलन शुरू किया है। इसको लेकर छात्र संघों व छात्र नेताओं का गुस्सा लगातार उबाल मार रहा है। छात्र राजनीति पूरी तरह ठप पड़ी है। छात्र नेताओं का कहना है लोकतंत्र का पहला दरवाजा छात्र संघ होता है। छात्र संघ से युवा निष्पक्ष चुनाव, मतदान व प्रचार का ककहरा सीखते हैं। निर्वाचित छात्रसंघ न होने से छात्रों की समस्याएं अनसुनी रह जा रही हैं और प्रतिनिधित्व का अभाव गहरी निराशा पैदा कर रहा है। छात्र संगठनों व छात्र नेताओं का आरोप है कि राज्य सरकार जान-बूझ कर चुनाव की प्रक्रिया को टालता आ रहा है। राजस्थान विश्व विद्यालय छात्र संघ देशभर में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है।

यहां के छात्र नेता सिर्फ युनिवर्सिटी अथवा कॉलेज तक सीमित नहीं रहते, बल्कि आगे चलकर देश और प्रदेश की राजनीति में अपनी अमिट छाप छोड़ते हैं। जो इस सीढ़ी को चढ़ गया वह राजनीति के ऊंचे मुकाम तक पहुंच जाता है। छात्र संघ के कई नेता बाद में राजनीति के दिग्गज चेहरे भी बने हैं। प्रदेश में कई साल से छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं, लेकिन आज भी प्रदेश की सियासत में छात्र राजनीति से निकले

नेताओं का बोल बाला है। छात्र संघ चुनाव में राजनीति का पहला ककहरा सीखा जाता है। केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक तक हर स्तर पर प्रभावशाली नेता दिए हैं। छात्र संघ की जड़ें गहराई तक फैली हुई हैं, जो न केवल छात्रों की समस्याओं के समाधान का मंच रहा है, बल्कि प्रदेश की सियासत को भी दिशा देने वाला स्तंभ साबित हुआ है। समय की माँग है कि छात्र संघ को फिर से जीवित किया जाए।

पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने विधानसभा चुनावों के मधे नज़र राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में होने वाले छात्रसंघ चुनावों पर रोक लगा दी थी। अब कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत छात्र संघ चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। गहलोत ने ही अपने कार्यकाल में चुनावों पर रोक लगाई थी जो भाजपा सरकार के दौरान भी बंदसतूर जारी है। राज्य की राजनीति में आज भी कई ऐसे नेता उच्च पदों पर आसीन हैं, जिन्होंने छात्र राजनीति से अपना सियासी सफर शुरू किया है। आज देश की लगभग 60 प्रतिशत आबादी युवा है। जो अपने माताधिकार का उपयोग कर देश तथा प्रदेश की सरकारें बनाती हैं। इतनी बड़ी आबादी का वोट सरकारें तय करती हैं। दूसरी तरफ छात्र संघों के चुनाव प्रदेशभर में प्रतिबंधित है। यह विचारणीय है।

एक छात्र नेता ने युनिवर्सिटी की राजनीति से निकले राजस्थान के प्रसिद्ध नेताओं के कटआउट लगाकर अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया और छात्र संघ चुनाव की मांग की। राजस्थान विश्वविद्यालय में लगाए कटआउट के जरिये बताया गया कि अनेक नेता और मंत्री छात्र संघों के जरिये सियासत में अपनी मजबूत स्थिति संभाले हुए हैं। छात्र संघ चुनाव की बंदौलत ही आज देश और प्रदेश को ऐसे संघर्षशील नेता मिलें है जो हर परिस्थिति में पीड़ितों और शोषितों की आवाज मजबूती से उठाते हैं। छात्र नेताओं का कहना है कि छात्रसंघ गहलोत, डॉक्टर सीपी जोशी, कालीचरण सराफ, हनुमान बेनीवाल, रघु शर्मा, सतीश पुनिया, प्रताप सिंह खाचरियावास, विकास चौधरी, महेंद्र चौधरी, रविंद्र सिंह भाटी, मनीष यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र राठी, अशोक लाहोटी, हरीश चौधरी, राजपाल सिंह शेखावत, रामलाल शर्मा,मुकेश भाकर, रामनिवास गवाड़िया, अभिमन्यु पुनिया और राजकुमार शर्मा के कट-आउट लगाये थे। सरकार ने लिंगदोह समिति की

शर्तों की पालना नहीं होना भी चुनाव नहीं कराने का एक कारण बताया है। देखा जाता है छात्र संघ चुनावों में लिंगदोह समिति की अचार संहिता की सरेआम धज्जियां उड़ाई जाती है। चुनाव एक मखौल बनकर रह जाता है। जाति और धनबल का खुला प्रदर्शन देखने को मिलता है। हिंसात्मक घटनाएं आम हो गई हैं। लिंगदोह समिति ने देश के विश्वविद्यालयों में होने वाले छात्रसंघ चुनावों के लिए कुछ सिफारिशें जारी की थीं, जिनका उद्देश्य बाहुबल और धनबल के प्रभाव को रोकना और चुनाव प्रक्रिया को सुचारु रूप से चलाना था। सिफारिशों के अनुसार, कोई छात्र केवल एक बार चुनाव लड़ सकेगा, और चुनाव में अधिकतम 5,000 रुपये खर्च किए जा सकेंगे। उम्मीदवार और उनके संगठन पर चुनावी चंदा लेने पर प्रतिबंध रहेगा। चुनाव में सर्वजनिक स्थानों पर पोस्टर, विज्ञापन और बैनर पर पूरी तरह प्रतिबंध होगा। कॉलेज परिसर में किसी प्रकार के हथियार लाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने पर उम्मीदवार पर दो साल का प्रतिबंध लगाया जाएगा, और उस साल की परीक्षा में भी वह वंचित हो जाएगा। वास्तविकता में लिंगदोह समिति की सिफारिशें कागजों में दबकर रह गई हैं।

–बाल मुकुन्द आन्ना,
वरिष्ठ लेखक एवं पत्रकार

ब्लैक बोर्ड से स्मार्ट बोर्ड का सफर – राजकीय विद्यालयों में स्मार्ट शिक्षा की ओर बढ़ते कदम



डॉ. अमृता कटार्रा

जयपुर। राजस्थान के राजकीय विद्यालय अब परंपरागत शिक्षण विधियों से आगे बढ़कर डिजिटल युग में प्रवेश कर चुके हैं। ब्लैकबोर्ड और किताबों की सीमाओं को पीछे छोड़ते हुए अब कक्षाएं स्मार्ट स्क्रीन, प्रोजेक्टर और डिजिटल कंटेंट से सजी हैं। राज्य सरकार की सूचना एवं संचार तकनीक योजना के तहत वर्ष 2024 तक 13,976 सरकारी विद्यालयों में

आईसीटी लैब्स की स्थापना की जा चुकी है। इनमें से 13,411 लैब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर कार्यरत हैं जबकि 565 आदर्श विद्यालयों की भी इस नेटवर्क से जोड़ा गया है। प्रदेश के 13 हजार से अधिक विद्यालयों में 17,421 स्मार्ट क्लासों की स्थापना भी की गयी है।

इन लैब्स के माध्यम से विद्यार्थी अब बेसिक कंप्यूटर ज्ञान के साथ ई-मेल, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट आदि सॉफ्टवेयर पर कार्य करना, इंटरनेट सर्फिंग, विषय आधारित वीडियो लेक्चर देखना और इंटरएक्टिव डिजिटल कंटेंट से परिचय भी सीख रहे हैं। इससे खासतौर पर ग्रामीण व दूरस्थ अंचलों के विद्यार्थी तकनीकी साक्षरता की ओर अग्रसर हो रहे हैं और राष्ट्रीय व वैश्विक स्तर की शिक्षा से जुड़ने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं।

शिक्षक- विद्यार्थी दोनों हो रहे डिजिटल रूप से दक्ष-ये प्रयोगशालाएं केवल उपकरणों का जमावड़ा भर नहीं हैं बल्कि यह एक

सशक्त डिजिटल कक्षा के रूप में विकसित की गई हैं, जहां विद्यार्थियों में तकनीकी दक्षता के साथ-साथ आत्मविश्वास, संवाद कौशल और निर्णय लेने की क्षमता जैसे जीवनोपयोगी गुणों का भी विकास हो रहा है। प्रत्येक लैब में कंप्यूटर, प्रिंटर, यूपीएस, आवश्यक शैक्षिक सॉफ्टवेयर और इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्था की गई है। साथ ही फर्नीचर, पावर बैकअप और सुरक्षा के मानकों का भी ध्यान रखा गया है ताकि तकनीकी शिक्षण में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।

राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक विद्यालय में एक प्रशिक्षित आईसीटी प्रभारी शिक्षक की नियुक्ति की गई है जो न केवल लैब का संचालन करते हैं बल्कि विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षण में मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। यह शिक्षक समय-समय पर विद्यालय के अन्य स्टाफ व प्रशासन को भी डिजिटल उपकरणों के प्रभावी उपयोग हेतु प्रशिक्षित कर रहे हैं जिससे विद्यालय समग्र रूप से डिजिटल

रूपांतरण की दिशा में अग्रसर हो रहा है।

तकनीक बनी सीखने का माध्यम- आज के विद्यार्थी केवल पाठ्यपुस्तकों तक सीमित नहीं हैं। वे इंटरनेट के माध्यम से विषयवस्तु की खोज करने, डिजिटल नोट्स तैयार करने, वस्तुअल विज्ञान में भाग लेने और ऑनलाइन कक्षाओं का हिस्सा बनने में पूरी तरह सक्षम हो रहे हैं। आईसीटी लैब्स एवं स्मार्ट क्लास ने विद्यार्थियों के भीतर आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दिया है। अब विद्यार्थी कंप्यूटर को केवल गेमिंग या मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि अपने भविष्य निर्माण का एक शक्तिशाली औज़ार समझने लगे हैं। राज्य के शिक्षा अधिकारियों द्वारा विभिन्न विषयों पर ई-क्लास वीडियो, एनिमेटेड प्रजेन्टेशन और पावरपॉइंट लेक्चर जैसे डिजिटल कंटेंट समय-समय पर तैयार किए जा रहे हैं। ये सामग्री आईसीटी लैब्स के माध्यम से विद्यार्थियों तक पहुंचाई जाती है। इससे न केवल विद्यार्थियों की

समझ में सुधार हुआ है बल्कि विज्ञुअल लर्निंग के कारण उनकी याददास्त और विषय पर पकड़ भी पहले से बेहतर हो रही है। यह दृष्टिकोण परंपरागत शिक्षा प्रणाली से हटकर एक सहभागी और बहुआयामी शिक्षण वातावरण की ओर बढ़ता कदम है।

मॉडल राज्य के रूप में स्थापित होगा राजस्थान -शिक्षा विभाग के प्रयास और सूचना एवं संचार तकनीक के माध्यम से राज्य के राजकीय विद्यालय अब डिजिटल इंडिया की रफ्तार से कदमताल कर रहे हैं। आईसीटी लैब्स और स्मार्ट क्लास न केवल विद्यार्थियों को तकनीकी रूप से सशक्त बना रही हैं बल्कि उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार कर रही हैं। यह पहल राजस्थान को न केवल डिजिटल शिक्षा में आत्मनिर्भर बनाएगी बल्कि पूरे देश के लिए एक मॉडल राज्य के रूप में स्थापित करेगी।

–डॉ. अमृता कटार्रा,
सहायक सूचना एवं
जनसंपर्क अधिकारी, सूचना एवं
जनसंपर्क विभाग

मीरा महोत्सव में उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने मीरा बाई के दर्शन किये

मेड़ता सिटी, (निसं)। विश्व ऐतिहासिक चारभुजानाथ के 521वें मीरा जयंती महोत्सव में उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने शिरकत की।

महोत्सव में उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने चारभुजानाथ व रजत रेवाड़ी के दर्शन कर महिलाओं के साथ भजनों का लाभ उठाया व महोत्सव में मीरा स्मारक के कार्यक्रम में मुख्यातिथि के रूप में मौजूद रही। वहीं महिला बाल विकास मंत्री मंजू बाघमार, किसान आयोग अध्यक्ष सीआर चौधरी, मेड़ता विधायक लक्ष्मणराम कलरू, खीवसर विधायक रवेतराम डांग, जनता प्रधान संदीप चौधरी, मेड़ता नगरपालिका अध्यक्ष शोभा लाहोटी, किन्नर समाज गादीपति राजकुमारी बाई कार्यक्रम में अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस अवसर पर मीरा जयंती महोत्सव समिति के अध्यक्ष व पूरी टीम के द्वारा उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी को स्मृति चिन्ह देकर अभिनंदन किया गया। मीरा महोत्सव में उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने मीरा बाई के दर्शन किये।

इस मौके पर दीया कुमारी ने अपने उद्बोधन में कहा कि मेड़ता मीरा की नगरी है, यहां आने का मौका इस



मीरा महोत्सव में उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने महिलाओं के साथ भजनों का आनंद लिया।

महोत्सव में ही मिलता है। दीया कुमारी ने कहा कि मेड़ता में जो भी विकास कार्य होंगे वो गुणवत्ता के साथ होंगे। मेड़ता में एक पैरोनामा जल्द ही बनने जा रहा है, उसकी डीपीआर तैयार हो रही है। भारत सरकार व राजस्थान सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए

भी कार्य कर रहे हैं। वहीं जहां पर कोई भगवान या भक्त सहित कई लोगों के सन्तिल उनके नाम से निर्माण कराने का प्रस्ताव जन प्रतिनिधियों द्वारा आयेगा उस पर कार्य किए जाएंगे। महिला बाल विकास मंत्री मंजू बाघमार ने कहा मेड़ता भक्ति भाव की

नगरी है। यहां के नागरिक प्रेम भाव से भरे हुये हैं। मेड़ता विधायक लक्ष्मणराम कलरू ने कहा कि उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी द्वारा मीरा महोत्सव को सरकारी कैलेंडर में स्थान दिलाने पर पूरा मेड़ता इनका आभारी है। मेड़ता से इनका सम्न्ध पुराना है।

- ‘मेड़ता में एक पैरोनामा जल्द ही बनने जा रहा है, उसकी डीपीआर तैयार हो रही है’
- दीया कुमारी ने चारभुजानाथ व रजत रेवाड़ी के दर्शन कर महिलाओं के साथ भजनों का लाभ उठाया

इसलिए मेड़ता क्षेत्र में विकास की गंगा बही है और गुणवत्ता के साथ सड़कों का निर्माण करवाया है। इस मौके पर उपखंड अधिकारी पूनम चोयल, जितेंद्र गहलोत मीरा महोत्सव समिति अध्यक्ष, सचिव विप्रकाश कमेडिया, विरमदेव सिंह जैसास, अभय सिंह भेसड़ा, ऋषभ राठी, लोक अभियोजक अभिमन्यु शर्मा, उमा शर्मा रजत, दशरथ सारस्वत, कैलाश गौड़, मोहित माली, रवि गहलोत सहित कई लोग मौजूद थे।



पंडित अनिल शर्मा

मिथुन, शुक्र-मिथुन, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में। आज सर्वोच्च सिंधि योग सूर्योदय से प्रातः 9:13 तक है। रवियोग सम्पूर्ण दिन-रात रहेगा। धनरा रात्रि 12:47 से आरम्भ होगी। आज चतुर्थ सावन वन सोमवार व्रत है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: अमृत सूर्योदय से 7:36 तक, शुभ 9:15 से 10:54 तक, चर 2:12 से 3:51 तक, लाभ-अमृत 3:51 से सूर्यास्त तक। राहूकाल: 7:30 से 9:00 तक। सूर्योदय 5:56, सूर्यास्त 7:09

राशिफल

सोमवार 4 अगस्त, 2025

सावन मास, शुक्ल पक्ष, दशमी तिथि, सोमवार, विक्रम संवत 2082, अनुराधा नक्षत्र प्रातः 9:13 तक, ब्रह्म योग प्रातः 7:05 तक, गर करण दिन 11:42 तक, चन्द्रमा आज वृश्चिक राशि में संसार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-कर्क, चन्द्रमा-वृश्चिक, मंगल-कन्या, बुध-कर्क, गुरु-

मिथुन, शुक्र-मिथुन, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में। आज सर्वोच्च सिंधि योग सूर्योदय से प्रातः 9:13 तक है। रवियोग सम्पूर्ण दिन-रात रहेगा। धनरा रात्रि 12:47 से आरम्भ होगी। आज चतुर्थ सावन वन सोमवार व्रत है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: अमृत सूर्योदय से 7:36 तक, शुभ 9:15 से 10:54 तक, चर 2:12 से 3:51 तक, लाभ-अमृत 3:51 से सूर्यास्त तक। राहूकाल: 7:30 से 9:00 तक। सूर्योदय 5:56, सूर्यास्त 7:09



मेघ

पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। परिवार में स्वास्थ्य परेशानी हो सकती है। आज बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। व्यावसायिक खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है।



तुला

आर्थिक कारणों से अटक हुए व्यावसायिक कार्य बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। धन-अमृत 3:51 से सूर्यास्त तक। राहूकाल: 7:30 से 9:00 तक। सूर्योदय 5:56, सूर्यास्त 7:09



वृष

परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक खर्चों में अनावश्यक व्यय में सुधार होगा।



वृश्चिक

व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटक हुए कार्य बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन हो सकता है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



मिथुन

स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। किसी भी कारण से बना हुआ मन का भय समाप्त होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है।



धनु

घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।



कर्क

परिजनों के व्यवहार के कारण मन खिन्न हो सकता है। आवश्यक कार्यों के संबंध में दुविधा बनी रहेगी। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित वार्ता सफल रहेगी। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी।



मकर

आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। धन में वृद्धि होगी। अटका हुआ अथ प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित प्रेरणा मिलेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



सिंह

घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। परिवार में आपसी अनबन-मतभेद हो सकते हैं। अतिथियों से आगमन से दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो सकती है।



कुंभ

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। अटक हुए कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



कन्या

आर्थिक/वित्तीय मामलों में परिचितों से सहयोग मिल सकता है। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में उचित सफलता मिल सकती है।



मीन

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटक हुए कार्य बनने लगेंगे। धार्मिक स्थानों की या

कालोटा में दबिश देने गई वन विभाग की टीम पर खनन माफिया ने पत्थर बरसाये

टीम ने खेतड़ी, चिड़ावा और झुंझुनूं रेंज के स्टाफ के साथ कालोटा गांव में दबिश दी

झुंझुनूं, (निसं)। जिले के खेतड़ी इलाके के कालोटा गांव में रविवार को कार्रवाई करने गई वन विभाग की टीम के सामने खनन माफिया हो गए। टीम पर ना केवल पत्थर बरसाए गए, बल्कि करीब पांच किलोमीटर तक वन विभाग की गाड़ियों और जब्त ट्रैक्टरों को छुड़वाने के लिए दो दर्जन से अधिक बाइकों पर सवार युवकों ने विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों को धमकियां दी।

एसीएफ कमलचंद ने बताया कि काफी दिनों से सूचना मिल रही थी कि कालोटा वन क्षेत्र स्थित पहाड़ी में अवैध खनन माफिया सक्रिय हो रहे हैं, जिस पर झुंझुनूं डीएफओ गुलजारीलाल जाट के निर्देशन में रविवार को खेतड़ी, चिड़ावा और झुंझुनूं रेंज के स्टाफ के साथ कालोटा गांव में दबिश दी गई। टीम मौके पर पहुंची तो वहां पर करीब डेढ़ दर्जन ट्रैक्टरों में अवैध चेजा पत्थर भरा हुआ था, लेकिन टीम को देखकर सभी ट्रैक्टर इधर-उधर भाग गए। मौके पर टीम ने चार ट्रैक्टरों को पकड़ा और उन्हें अपने साथ ले जाने लगे तो पहाड़ी में छुपे खनन माफियाओं ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, जिसके चलते महिला वनकर्मी और वाहन बाल-



वन विभाग की टीम ने दो ट्रैक्टरों को जब्त कर चालक को गिरफ्तार किया।

बाल बचे। टीम ने जैसे तैसे दो ट्रैक्टर और एक आरोपी को अपने साथ लिया और मौके से रेंज कार्यालय खेतड़ी के लिए रवाना हुए। रेंजर विजय कुमार फगेड़िया ने बताया कि खनन माफियाओं में किसी प्रकार का खौफ नहीं दिखा, जिस आरोपी शीशराम को वन विभाग की टीम ने पकड़ा था, उसका ही सगा भाई भागीरथ बाइक पर अपने साथियों के साथ आया। भागीरथ और उसके साथ

बड़ी संख्या में युवक करीब दो दर्जन बाइकों पर सवार थे, जिन्होंने कालोटा से लेकर बबाई तक, करीब पांच किलोमीटर तक वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को धमकाने और डराने की कोशिश की। साथ ही जब्त ट्रैक्टर और अपने भाई को छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे। वन विभाग की टीम को चलती बाइक से धमकी देने और भारी संख्या में बाइकों को गाड़ियों के

आगे पीछे दौड़ने का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि खेतड़ी इलाके में खनन माफियाओं की हद तक बेखौफ हो चुके हैं। वहीं टीम ने दो ट्रैक्टरों को जब्त कर शीशराम नाम के चालक को गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज कार्रवाई शुरू कर दी है। कार्रवाई टीम में एसीएफ कमलचंद, रेंजर विजय फगेड़िया, वनपाल संजय कुमार,

■ पांच किमी तक वन विभाग की गाड़ियों और जब्त ट्रैक्टरों को छुड़वाने के लिए दो दर्जन से अधिक बाइक सवार युवकों ने अधिकारियों व कर्मचारियों को धमकियां दी

■ वन विभाग की टीम को चलती बाइक से धमकी देने और भारी संख्या में बाइकों को गाड़ियों के आगे-पीछे दौड़ने का वीडियो भी वायरल हो रहा है

सत्यवीर झाझड़िया, सहायक वनपाल पिंकू कुमार, मनोज कुमार मीणा, ओमप्रकाश, वनरक्षक भारत कुमार, सुमेर सिंह, राधेश्याम गुर्जर, कविता कुमारी, सुमन कुमारी, महेंद्र सिंह, वाहन चालक रामकुमार, महिपाल सिंह इत्यादि मौजूद रहे।

नीमकाथाना क्षेत्र के अधिकांश गांवों के लोग फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर

ग्रामीणों ने समस्या के बारे में अनेक बार विभागीय अधिकारियों से लेकर स्थानीय प्रशासन को भी अवगत कराया, पर कोई ध्यान नहीं दिया गया

पाटन, (निसं)। प्रदेश के कई ग्रामीण अंचलों में लोग वर्षों से फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर हैं। नीमकाथाना क्षेत्र के अधिकांश गांव के लोगों को फ्लोराइड युक्त पानी पीना पड़ रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने अनेक बार विभागीय अधिकारियों से लेकर स्थानीय प्रशासन को भी अवगत कराया, परंतु प्रशासन ने भी इस गंभीर समस्या के समाधान की तरफ ध्यान नहीं दिया। इतनी बड़ी समस्या के बावजूद भी न तो कोई सुनने वाला है और न ही कोई बोलने वाला है। राजस्थान और हरियाणा समेत केंद्र में भी भाजपा की सरकार होने के बावजूद

■ बहुप्रतीक्षित कुंभाराम लिफ्ट परियोजना यदि शुरू हो जाती, तो हजारों लोगों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल मिल सकता था

■ ग्रामीणों का कहना है कि फ्लोराइड युक्त पानी पीने से बच्चों और युवाओं में हड्डियों की कमजोरी, दांतों का खराब होना और अन्य शारीरिक विकृतियां तेजी से फैल रही हैं

बहुप्रतीक्षित कुंभाराम लिफ्ट परियोजना को अभी तक धरातल पर नहीं लाया गया है। यह परियोजना यदि शुरू की जाती, तो हजारों लोगों को स्वच्छ और सुरक्षित

पेयजल मिल सकता था। परंतु स्थितियां उस की तस बनी हुई हैं। ग्रामीणों का कहना है कि फ्लोराइड युक्त पानी पीने से बच्चों और युवाओं में हड्डियों की

कमजोरी, दांतों का खराब होना और अन्य शारीरिक विकृतियां तेजी से फैल रही है। इसके साथ ही इलाके में लगातार उड़ती धूल और मिट्टी ने लोगों की सेहत को और खराब कर दिया है। डोकण निवासी मनिष चतुर्वेदी ने निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि सिर्फ योजनाएं बनती हैं, लेकिन जमीन पर कुछ भी नहीं दिखाई देता। कुंभाराम लिफ्ट परियोजना जैसे जल जीवनदायिनी प्रयास को शीघ्र शुरू किया जाना नितांत आवश्यक है, ताकि आमजन को राहत मिल सके और आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित भविष्य दिया जा सके।

नीट परीक्षा में अच्छे नंबर दिलाने का झांसा देकर छात्र से 8.50 लाख ठगे

कोटा, (निसं)। शहर में मेडिकल पटेंट्स की कोर्चिंग करने आए बिहार के छात्र से नीट यूजी परीक्षा पास करवाने की एवज में लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। मामले में सामने आया कि आरोपी भी छात्र के दोस्त हैं, जिन्होंने उससे परीक्षा पास करवाने की एवज में लाखों रुपए ठग लिए। ठगी का मामला सामने आने पर जवाहर नगर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

मामले में सामने आया कि ठगी का पीड़ित छात्र बिहार के मुजफ्फरपुर के कुदनी थाना इलाके के मादापुर रायती निवासी है। उसकी दोस्ती दो लड़कों से हुई थी। पढ़ाई के दौरान कुछ परेशान रहने लगा तो इस पर दोनों दोस्तों ने नीट में अच्छे से अच्छे नंबर दिलाने का झांसा दिया। जिसके लिये 13 लाख रुपए की मांग की। इसके बाद छात्र ने अपनी बहन की शादी के लिए पिता की ओर से खाते में डाले हुए 8.50 लाख रुपए निकाल

कर आरोपी को दे दिए। जवाहर नगर थानाधिकारी रामलक्ष्मण ने बताया कि बिहार निवासी एक छात्र ने नीट की परीक्षा में अच्छे अंक दिलाने के नाम पर उससे साढ़े आठ लाख की ठगी होने की शिकायत दी। थानाधिकारी ने बताया कि मामले में परियादी छात्र व रूपये की ठगी करने वाला छात्र भी बिहार की निवासी है और दोनों दोस्त हैं। मामले में परियादी की शिकायत पर मामला दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

उदयपुर, (निसं)। उदयपुर में पुलिस ने बीस लाख की अवैध शराब मय पिकअप वाहन जब्त किया है। महानिरिक्षक पुलिस उदयपुर रेंज गौरव श्रीवास्तव के आदेश पर डीएसटी टीम प्रभारी श्यामसिंह रत्नू, डबोक थानाधिकारी हुकमसिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने मुखबीर से मिली सूचना पर ओडवाड़ीया से झंझेला मार्ग पर तालाब के पास श्मशान भूमि के तरफ रास्ते पर एकांत में पिकअप वाहन खड़ा

था। जिसका त्रिपाल हटा कर तलाशी ली तो उसमें 78 कर्टन अवैध शराब के पाए गए। इसी दौरान भैसड़ा कला में आबलिया का कुआं से भैसड़ा कला गांव रोड़ पर किशन पुत्र गणेश डांगी के मकान के पास बाड़े में होने पर मौके पर दबीश देकर 180 कर्टन अवैध शराब के जन्त कर प्रकरण दर्ज किया। इस दौरान किशन के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। बरामद शराब की बाजार कीमत बीस लाख रूपये बताई जाती है।

अजमेर, (कासं)। डीएवी कॉलेज के खेल मैदान में अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की मातृ शक्ति की ओर से मानसून फेस्ट का आयोजन किया गया। महिलाओं के लिए, महिलाओं द्वारा आयोजित यह उत्सव सशक्तिकरण, मनोरंजन और जागरूकता का संगम बना। इसमें महिलाओं के मनोरंजन के साथ-साथ विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं हुईं। विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। मानसून फेस्ट में महिलाओं

के साथ बच्चों के मनोरंजन का भी विशेष ध्यान रखा गया। बच्चों के विभिन्न प्रकार के झूले व 30-40 प्रकार की स्टॉलें लगाई गईं। विधायक अनिता भदेल ने बताया कि महिलाओं को जागरूक तथा उनके अधिकारों की जानकारी के लिए विप्रा ल विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शिविर का आयोजन किया गया। यहां पर महिलाओं को कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई। महिलाओं के स्वास्थ्य

संबंधी जानकारी के लिए स्वास्थ्य विभाग ने भी शिविर लगाया। साथ ही अन्य व्यवस्थाएं भी की गईं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया किशोर राहतकर, उम मुख्यमंत्री दीया कुमारी, राज्य मंत्री मंजू बाघमार, विधायक अनिता भदेल, लाडपुरा विधायक कल्पना देवी, राजसमंद विधायक दीपति किरण मोहेश्वरी, पूर्व विधायक अनिता सिंह गुर्जर आदि ने भी शिरकत की।

सैन्य प्रतिष्ठानों के पास अफीम तस्कर गिरफ्तार

बीकानेर, (कासं)। स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले बीकानेर में सेना की इंटेलिजेंस यूनिट और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक बड़ा नशा तस्करी रैकेट सामने आया है। इस कार्रवाई के दौरान बीकानेर के शोभासर सर्कल से 452 ग्राम अफीम के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। यह इलाका न केवल व्यावसायिक रूप से व्यस्त है बल्कि भारतीय सेना और वायुसेना के महत्वपूर्ण ठिकानों के बेहद करीब भी है। गिरफ्तार युवक की पहचान सुनील उपाध्याय पुत्र सत्यनारायण उपाध्याय निवासी मेघासर के रूप में हुई है। यह युवक पिछले 5 से 5 वर्षों से शोभासर चौराहे पर ब्राह्मण

बीलवाड़ा, (निसं)। शहर के उपनगर पुर में रविवार को अचानक उस वक्त मातम पसर गया, जब पता चला कि कि प्रदेश सरकार की 10-10 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा केवल औपचारिकता है। इस घटना के बाद प्रशासन ने अंतिम संस्कार में मां-बाप को भी शामिल नहीं होने दिया गया, जबकि प्लेन हादसे में प्रत्येक व्यक्ति को एक करोड़ का मुआवजा दिया। रोट ने कहा कि समाज के बच्चों को 10 लाख नहीं दिए हैं, यह सहायता तो सरकार की योजना है। सरकार ने अलग से कुछ नहीं दिया। केवल ड्रामा कर रहे हैं।



आरोप है कि बस्ती में ही पार्षद और प्रशासन की लापरवाही से क्षेत्र में बरसाती गड़्ढों में पानी भरा हुआ है जिसके चलते आए दिन हादसे हो रहे हैं। इसे ही एक बरसाती गड़्ढे में डूबने से शिफान की मौत हुई है।

■ सांसद राजकुमार रोट ने विरोध करने के मामले में बीजेपी पर निशाना साधा, कहा कि इस हंगामे के पीछे भाजपा संगठन से जुड़े लोग शामिल हैं, जो लोग मेरा विरोध कर रहे हैं

करने के मामले में बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस हंगामे के पीछे भाजपा संगठन से जुड़े लोग शामिल हैं, जो लोग मेरा विरोध कर रहे हैं। उन्हें बता दें कि मुझे झालावाड़ से चुनाव नहीं लड़ना। जो लोग मुझसे लड़ने आए, वह समाज के मानसिक विकलांग हैं, जो लड़ाई करने आए थे, उन पर बड़े राजनीतिक घरों के लोगों का श्रेय था। सांसद राजकुमार रोट ने कहा कि 2016 में हमला करने वाले आज हमारे साथ खड़े हैं। मैं अपने दावे के साथ कहता हूँ, आज जो भी आए थे, कुछ तो नासमझ थे। उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। उनको उकसाया गया, जो एक दिन साथ खड़े होंगे, जो हमसे भी साल पहले लड़ाई करने आए थे, जो भाई आज हमारे साथ खड़े हैं। उनके आज समझ आया, हमें खुशी है। जब 2016 में हम पर हमला हुआ था। हमारे साथी आज आसपुर से विधायक हैं। उनका हाथ फ्रैक्चर हुआ था। हमारे ही कुछ भाई जो मानसिक

रूप से दिव्यांग थे, उन्होंने किसी के कहने पर हमला कर दिया था। हालांकि खुशी इस बात की है कि आज वहीं भाई हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हमें बांट रहे हैं, लेकिन हमें अपने लिए लड़ना पड़ेगा और लड़ेंगे। स्कूल हादसे पर राजकुमार रोट ने कहा कि झालावाड़ स्कूल हादसे पर सरकार ड्रामा कर रही है। सांसद रोट ने झालावाड़ स्कूल हादसे पर भी प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की 10-10 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा केवल औपचारिकता है। इस घटना के बाद प्रशासन ने अंतिम संस्कार में मां-बाप को भी शामिल नहीं होने दिया गया, जबकि प्लेन हादसे में प्रत्येक व्यक्ति को एक करोड़ का मुआवजा दिया। रोट ने कहा कि समाज के बच्चों को 10 लाख नहीं दिए हैं, यह सहायता तो सरकार की योजना है। सरकार ने अलग से कुछ नहीं दिया। केवल ड्रामा कर रहे हैं।

झालावाड़, (निसं)। आदिवासी दिवस के अवसर पर झालावाड़ में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोट के आरक्षण पर दिए पूर्व के बयान पर भील समाज के ही एक अन्य गुट ने हंगामा कर दिया।



आदिवासी दिवस पर कार्यक्रम में पहुंचे सांसद का विरोध करने पर पुलिस व भील समाज के लोगों के बीच झड़प हुई।

अपने समर्थकों से हंगामा नहीं करने की अपील भी की, लेकिन इसी बीच कुछ लोगों ने पत्थर फेंक दिए और मौके पर भगदड़ मच गई। ऐसे में पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा तथा पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए पत्थरबाजों एवं हंगामा करने वाले लोगों को खदेड़ दिया। पत्थरबाजी में कुछ

पुलिसकर्मियों के चोटिल होने की बात भी सामने आई है। मौके पर कुछ बदमाश पुलिस पर बड़े-बड़े पत्थर उठाकर हमला कर रहे थे, ऐसे में पुलिस द्वारा जबरदस्ती बाहर निकाल गया। मामले में पुलिस द्वारा अरविंद भील सहित कुछ लोगों को डिटेन किया गया है।

हालांकि हंगामे के दौरान कई दो पहिया वाहन टूट गए तथा भागदड़ के दौरान लोग आसपास के घरों में घुस गए, जहां से अराजक तत्वों को पुलिस द्वारा बाहर निकाला गया। पुलिस की घटना के बाद भील समाज के लोग भील समाज के लोगों के बीच झड़प हुई।

‘आर्थिक तंगी और बढ़ते कर्ज से किसान तबाह ओर बर्बाद हो रहा है’

कोटा, (निसं)। भारतीय राष्ट्रीय किसान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज दुबे की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय किसान महासभा की कोटा संभागीय कार्यकारिणी की आवश्यक बैठक सोगरिया में संगठन कार्यालय पर सम्पन्न हुई। जिसमे किसानों की विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक मे आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई।

बैठक को सम्बोधित करते हुए राष्ट्रीय

■ ‘अतिवृष्टि एवं जलभराव से खरीफ फसलों को हुए भारी नुकसान का तुरंत सर्व कर मुआवजा दे सरकार’



भारतीय राष्ट्रीय किसान महासभा की बैठक मनोज दुबे की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

खत्म होने के कगार पर है, किसान बर्बाद हो चुका है। राजस्थान सरकार प्रदेश को आपदाग्रस्त घोषित कर किसानो को आर्थिक सहायता देकर राहत दें।

मनोज दुबे ने कहा की अतिवृष्टि ने पूरे प्रदेश के किसानों को बर्बादी के कगार पर ला कर खड़ा कर दिया है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में किसानों की मेहनत पानी में बह गई है। खेत अब नदी ओर तालाब बन चुके हैं। किसान अपने खेतों को देख कर रो रहे हैं। आज जब किसान अपना सब कुछ खोने की कगार पर है, तब सरकार मौन है? सरकार ने अब तक भी नुकसान का सर्वे एवं मुआवजे का ऐलान नहीं किया जो घोर निंदनीय एवं दुर्भाग्य पूर्ण है।

मनोज दुबे ने कहा की किसानों को समय पर डीएपी एवं यूरिया खाद नहीं मिलने से खरीफ फसलों की बुआई मे देरी के बाद भारी बरसात किसानों के लिए आफत बन गई है। डूनेज सिस्टम सही नहीं होने से खेतों मे भारी जल भराव के कारण सोयाबीन, उड़द, तिल्ली आदी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। अधिकांश सब्जियां भी बर्बाद हो गई है। राजस्थान में हुई भारी बारिश से खरीफ की फसल खाव होने से किसानों परेशानी मे है। महंगी खाद, बीज हंकाई-जुताई कीटनाशक सब बर्बाद हो गया

है। जिसने धरतीपुत्रों के अरमाओं पर पानी फेर दिया है।

अतिवृष्टि से हुए जल भराव से किसानों की सोयाबीन, मक्का, उड़द, तिल्ली आदि फसल बर्बाद हो गई है। सरकार अति शीघ्र गिरदावरी करवाकर किसानों को उचित मुआवजा दें। मनोज दुबे ने कहा की सरकार किसानों को डीएपी और यूरिया खाद तक पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध कराने मे पूर्ण रूप से विफल रही है। नकली खाद, बीज ओर पेस्टिसाइड से किसानों की खेती बंजर हो रही है। लेकिन सरकार नकली खाद, बीज ओर कीटनाशक माफियाओ पर अंकुश लगाने मे भी नाकाम रही है। किसानों पर चौतरफा अत्याचार हो रहा है, ओर भाजपा की केंद्र एवं राज्य सरकार सरकार तमाशा देख रही है। जिससे किसानों मे भारी आक्रोश व्याप्त है। इस अवसर पर संभागीय अध्यक्ष राकेश कुमावत, त्रिलोक मीणा, सतार मंसूरी, इशराद खान, चन्द्र प्रकाश नागर (हरी पुरा) मुकेश मीणा, अब्दुल मोईन खान, लेखराम चौबदार, सहित कई वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। बैठक मे कोटा देहात अध्यक्ष हरभजन सिंह के आकरिस्मक निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या मे कार्यकार्य मौजूद थे।

जिले भर में दबिश देकर 205 आरोपी पकड़े

रावतभाटा, (निसं)। महानिरीक्षक पुलिस रेंज उदयपुर गौरव श्रीवास्तव के निर्देश पर जिला पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़, गिरफ्तारी व एरिया डोमिनैस के लिए रविवार को विशेष अभियान चलाकर जिले के समस्त पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों की 69 विशेष टीमों द्वारा विभिन्न संरिग्ध स्थानों पर दबिश देकर कार्रवाई करते हुए कुल 205 अपराधियों को गिरफ्तार किया है।

कार्यवाही के दौरान दो प्रकरण एनडीपीएस एक्ट, 06 प्रकरण आबकारी अधिनियम, एक प्रकरण आर्म्स एक्ट व एक प्रकरण आरएनसी एक्ट में दर्ज किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि महानिरीक्षक पुलिस उदयपुर रेंज गौरव श्रीवास्तव के निर्देश पर वांछित अपराधियों की धरपकड़, गिरफ्तारी एवं एरिया डोमिनैस के लिए एक विशेष

अभियान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चित्तौड़गढ़ सरिता सिंह के सुपरविजन में रविवार को संपूर्ण जिले में चलाया गया। वृत्तवार एवं थानावार अपराधियों की सूचीयां तैयार कर उनकी धरपकड़ के लिये अलग-अलग टीमों का गठन किया गया।

समस्त पुलिस उप अधीक्षकों से वांछित अपराधियों की सूची एवं दबिश टीम तथा दबिश स्थान चिन्हित कर उन्हे अंतिम रूप दिया गया एवं समन्वय स्थापित करते हुए धरपकड़ कार्यवाही की गई।

जिले के शहर चित्तौड़गढ़, ग्रामीण चित्तौड़गढ़, गंगार, कपासन, बेगु, रावतभाटा, बड़ीसादड़ी, निम्बाहेड़ा व भदेसर वृत्त के समस्त वृत्ताधिकारी एवं थानाधिकारियों के नेतृत्व में कुल 69 विशेष टीमें गठित की गई। जिसमें समस्त थाना, पुलिस लाईन के जाब्ता सहित पुलिस कर्मियों को एकत्रित किया गया। रविवार तड़के

कुल 323 पुलिसकर्मियों द्वारा जिले के 402 संदिग्ध स्थानों पर दबिश दी गई, जहां से विभिन्न मामलों में वांछित चल रहे स्याई वारंटी, गिरफ्तारी वारंटी, उद्घोषित अपराधी, धारा 299 सीआरपीसी में वांछित, विभिन्न प्रकरणों में वांछित एवं अन्य अधिनियमों सहित कुल 205 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जिनमें विभिन्न प्रकरणों के अपराध में वांछित 17 अपराधी, 100 स्याई वारंटी, मफरूरी में वांछित, गिरफ्तारी वारंटी, सामान्य प्रकरणों में वांछित 25 अपराधी सहित कुल 205 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। जिसमें सबसे अधिक ग्रामीण चित्तौड़गढ़ व भदेसर वृत्त में 41-41 अपराधियों को दबोचा गया। उक्त कार्यवाही के दौरान दो प्रकरण एनडीपीएस एक्ट, 06 प्रकरण आबकारी अधिनियम, एक प्रकरण आर्म्स एक्ट व एक प्रकरण आरएनसी एक्ट में दर्ज किया गया।

कोटा की बालिकाओं ने योगासन स्पर्धा में दमखम दिखाया, राज्य स्तर के लिए होंगी तैयार

कोटा, (निसं)। छठी कोटा योगासन स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप 2025 में राजकीय बालिका गृह की छह बालिकाओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विभिन्न वर्गों में शीर्ष स्थान प्राप्त किए।

सब-जूनियर ग्रुप में दो बालिकाओं ने भाग लिया, जिनमें से एक बालिका ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया, वहीं जूनियर ग्रुप में चार बालिकाओं ने भाग लेकर क्रमशः प्रथम,

तृतीय, चतुर्थ और पंचम स्थान पर अपनी प्रतिभा का परचम लहराया।

हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी संचेतन संस्था की भारती गौड़ द्वारा राजकीय बालिका गृह एवं नारी निकेतन की बालिकाओं को योग प्रतियोगिता में भाग दिलवाया गया और उन्हें प्रतियोगिता की विशेष तैयारी भी करवाई गई। राजकीय बालिका गृह की अधीक्षक अंशुल मेहंदीरता ने जानकारी दी कि पिछले कई वर्षों

से यहां की बालिकाएं योगासन प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं और विभिन्न स्तरों पर स्थान प्राप्त कर रही हैं।

बालिकाओं की इस उपलब्धि पर बाल कल्याण समिति, सहायक निदेशक रामराज मीणा एवं संरक्षक अधिकारी दिनेश शर्मा ने बालिकाओं को बधाई देते हुए राज्य स्तरीय प्रतियोगिता की तैयारी में जुटने हेतु प्रोत्साहित किया।

बहनों ने बांधी ऊर्जा मंत्री नागर की कलाई पर स्नेह की डोर

कोटा, (निसं)। सुबह से बीरबसी का व्रत कर अपने भाईयों की उन्नति, प्रगति और समृद्धि की कामना कर रही महिलाओं को लाड़ले भाई ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का साथ मिला। लाड़ली बहना रक्षासूत्र समारोह के दौरान ऊर्जा मंत्री को भाई के रूप में अपने बीच पाकर प्रफुल्लित थी।

देवली और कनवास भाजपा मण्डल का लाड़ली बहना रक्षासूत्र समारोह रविवार को दरा रोड़ कनवास स्थित खेल ग्राउंड में आयोजित किया गया। जहां बहनों ने अपने साथ लाए रक्षा सूत्र और श्रीफल के साथ राखी बांधी। बहनें ऊर्जा मंत्री के मस्तक पर रोली और अक्षत का टीका लगाकर बलाइयां लेती रहीं। वेद विद्यालय के छात्रों ने वैदिक मंत्रोच्चारण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। समारोह को संबोधित करते हुए ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि ईश्वर की कृपा से ऐसा संयोग बना है कि आज बीरबसी के

■ बीरबसी के व्रत पर बहनों को मिला भाई का साथ

■ कनवास में लाड़ली बहना रक्षासूत्र समारोह सम्पन्न



ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बहनों से रक्षा सूत्र बंधवाए।

कर रहे हैं। वहीं उद्योग और उत्पादों को मार्केट दिलाने के लिए भी कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि पहले जब दूधियाखेड़ी मालाजी पर कार्यक्रम किया था तो कांग्रेस के लोगों ने उसे वोट से जोड़ा था, लेकिन मैं आपको यह विश्वासपूर्वक कहता हूँ कि आपसे विश्वास और प्रेम की यह डोर सब बंधी रहेगी। इस डोर को कभी टूटने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि हमारी आने वाली पीढ़ियां स्वस्थ और सशक्त बनें, इसके लिए सुपोषित मां अभियान की शुरुआत की है। गर्भवती बहनें स्वस्थ रहें। उनका बच्चा स्वस्थ हो, यह हमारा संकल्प

है। पोषण किट के साथ स्वास्थ्य जांच और दवा देने का काम भी करेंगे।

इस अवसर पर जिला प्रमुख मुकेश मेघवाल, प्रधान जयवीर सिंह अमृतकुआं, उप प्रधान ओम नागर अडुसा, अंजना मीना, धनराज मीणा, आशा त्रिवेदी, मंडल अध्यक्ष सत्यवान नागर, विजयशंकर सैनी, पूजा कुमारी, गुड्डी बाई, दुर्ग्यंत शर्मा, नरेंद्र मोहन गौतम, हेमलता, महावीर, दुर्गाशंकर गुर्जर, नंदकिशोर मालव, शिवराज मालव, ईश्वर मालव, कोशल सोनी, धनराज नागर समेत कई लोग मौजूद रहे।

‘सामाजिक संस्थाएं समाज के दुख, दर्द, पीड़ा में सहयोगी बनें’

कोटा, (निसं)। श्री कल्याणराय किराड़ क्षत्रिय विकास समिति की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथग्रहण समारोह रविवार को श्रीनाथपुरम स्थित किराड़ छात्रावास पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर थे। अध्यक्षता कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने की। इस दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला प्रमुख मुकेश मेघवाल, क्षत्रिय किराड़

महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री रामकुमार मेहता, रेल सलाहकार बोर्ड के सदस्य आशीष मेहता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम मेहता, महासभा के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास मेहता, पूर्व सरपंच शिवराम मेहता मौजूद रहे। इस दौरान नवनिर्वाचित अध्यक्ष गोविंद मेहता, युवा अध्यक्ष मनीष मेहता, महिला अध्यक्ष सुनीता मेहता की नवनियुक्त कार्यकारिणी ने शपथग्रहण की। संबोधित करते हुए ऊर्जा मंत्री

हीरालाल नागर ने कहा कि सभी समाज संगठित होकर राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी निभाएं। राष्ट्र निर्माण के लिए हमें सर्वसमाज को साथ लेकर सबके विकास और हित की बात करनी होगी। हम सभी मिलकर राष्ट्र की उन्नति में योगदान दें। यह समय की आवश्यकता भी है। सभी सामाजिक संस्थाएं समाज के दुख, दर्द, पीड़ा में सहयोगी बनें। विधायक संदीप शर्मा ने कहा कि किराड़

समाज राष्ट्रवादी समाज है। जो सनातन की रक्षा की भूमिका में रहा है। किराड़ समाज खेती किसानों के साथ-साथ शिक्षा और व्यापार में भी आगे बढ़ रहा है। आशीष मेहता ने कहा कि किराड़ समाज अन्न उपजाकर देश की सेवा कर रहा है। गाँव ढाणी में रहने वाले नौजवान को अच्छी शिक्षा के द्वारा आगे बढ़ाया जा सकता है। सभी मिलकर समाज की एकता, उन्नति और विकास के लिए कार्य करें।

Government of India	
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE	
Regional Office, Gandhinagar, A Wing-407 & 409, "Aranya Bhawan", Near Ch-3 Circle, Sector-10a, Gandhi Nagar-382010	
Email: Iro.gandhinger-mefcc@gov.in	
Online Proposal No. - FP/RJ/ROAD/488019/2024	Dated : 01/07/2025
To,	
Principal Secretary (Forest and Environment), Department of Forest and Wildlife Government of Rajasthan Vaniki Path, Near Secretariat Jaipur-302005 (Rajasthan)	
Subject :	Proposal for non-forestry use of 1.71 ha of forest land under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 in favour of M/s PUBLIC WORKS DEPARTMENT for Baran Territorial Division in Forest Division, District BARAN (RAJASTHAN)
Name of Road - Garda Gopalpura To Rajakhera	
Sir/Madam,	
This is in reference to the online proposal no. FP/RJ/ROAD/488019/2024 dated 15/07/2024 on the above- mentioned subject seeking prior approval of the Central Government in accordance with section'2 of the Van (Samrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and to say that the proposal has been examined by Regional Office, as per extant rules and regulations. After the examination, the undersigned directed to convey the " In-Principle/Stage-I " approval of the Central Government under section 2 of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 for the proposal for non-forestry use of 1.71 ha of forest land under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 in favour of M/s PUBLIC WORKS DEPARTMENT for Baran Territorial Division in Forest Division, District BARAN (RAJASTHAN) subject to the fulfillment of the following condition :	
1. General Conditions	
S.No.	Conditions
1.1	Compensatory afforestation over the degraded forest land double in extent to the forest land being diverted shall be raised and maintained by the State Forest Department at the cost of the User Agency; Or Compensatory afforestation over the non-forest land equal in extent to the forest land being diverted shall be raised and maintained by the State Forest Department at the cost of the User Agency
1.2	Legal Status of the diverted foret land shall remain unchanged
1.3	The non-forest land identified for raising compensatory afforestation shall be transferred and mutated in favour of the State Forest Department before issue of the Stage-II clearance
1.4	The non-forest land transferred and mutated in favour of the State Forest Department shall be notified by the State Government as RF under section-4 or PF under Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevent section(s) of the local Forest Act, 1927 latest within a period of six months from the date of issue of Stage-II approval. The Nodal Officer shall report compliance in this regard along with a copy of the original notification declaring the non-forest land under section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, as the case may be, within the stipulated period to the Central Government for information and record
1.5	The land identified for the purpose of CA shall be clearly depicted on a Survey of Indian toposheet of 1:50,000 scale
1.6	The User Agency shall transfer the cost of raising and maintaining the compensatory afforestation, at he current wage rate, to the State Forest Department. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.
1.7	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in Writ Petition (Civil) No. 202/1995 and the guidelines issued by this ministry vide its letter No. 5-3/2007-FC dated 05.02.2009 in this regard
1.8	At the time of payment of the Net Present Value (NPV) at the then prevailing rate, the User Agency shall furnish as undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India.
1.9	All the funds received from the user agency under the project, except the funds realized for regeneration/ demarcation of safety zone, shall be trasferred to Ad-hoc CAMPA in the Savings Bank Account pertaining to the State concerned.
1.10	The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required.
1.11	The boundary of the diverted forest land, shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, forward and back bearing and distance from pillar to pillar
1.12	The User Agency, if required, will undertake comprehensive soil conservation measures in the area being diverted at the project cost in consultation with the State Forest Department. A scheme of the same may be submitted along with the compliance report
1.13	No labour camp shall be established on the forest land (Cont.)

1.14	The User Agency shall provide fuels preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas
1.15	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal
1.16	The layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government
1.17	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Central Government
1.18	No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused
1.19	Any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision of the State Forest Department
1.20	The State Government shall complete settlement of rights, in terms of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, if any, on the forest land to be diverted in accordance with the relevant guidelines issued by the MoEF
1.21	The user agency in consultation with the State Government shall create and maintain alternate habitat/home for the avifauna, whose nesting trees are to be cleared in this project. Bird's nests artificially made out of eco-friendly material shall be used in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project
1.22	The User Agency shall submit six monthly self-compliance reports as on 1st January and 1st July of every year to this office as well as to the Nodal Officer of the State
1.23	The State Government shall monitor compliance of conditions of Forest Clearance and shall submit in this regard yearly report as on 31st December of every year
1.24	Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate, from time to time, in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife
1.25	The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of the all Acts, Rules, Regulations and Guidelines, for the time being in force, as applicable to the Project
1.26	Grant of working permission to the extant proposal may be considered by the State Government in accordance with the provisions as contained in the MoEF&CC's Guidelines dates 28.08.2015
1.27	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 1.71 ha NFL , Survey/Khasra No.-369, Village-Takha, Tehsil-anta, District-Baran of Rajasthan at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and mono-culture of any species may be avoided.
1.28	Nil tree felling shall be involved in the implementation of this project.
1.29	If the proposed area is part/out side of any Wildlife Sanctuary/National Park, User Agency shall be obtained Wildlife Clearance from competent authority as per the provisions of the extant, rules and regulation.

2. Standard Conditions

S.No.	Conditions
2.1	The User Agency shall arrange to raise strip platation on either side of the road and central verge at project cost, as per IRC specification, with maintenance of 7-10 Years. The user agency shall also submit design of providing at least 2-3 rows of long rotation indigenous trees, as per provision of IRC-SP-21-2009 (Guidelines on landscaping & tree plantation), on either side of the road before final clearance.
2.2	The reclamation of quarry should be done under the supervision of the State Forest Department. The quarry shall be reclaimed and afforested completely before the project is closed.
2.3	Overburden shall not be dumped outside the width of the road. The muck generated in the earth cuttings will be disposed of at the designated dumping sites and in no case the muck/debris will be allowed to roll down the hill slopes.
2.4	The user agency will provide retaining walls, breast walls and drainage as per requirement to make the slope stable.
2.5	The User Agency will undertake comprehensive soil conservation measures at the project cost in consultation with the State Forest Department. A scheme of the same shall be submitted to the Regional Office along with the Stage-I compliance report;
2.6	The designing of culverts/bridges, if any, over the natural streams/rivers/canals should be done in such a manner that it does not hamper the natural course of water, does not give rise to water-logging, and also does not hamper movement of wild animals.

3. Specific Conditions

S.No.	Conditions
3.1	The User Agency shall Construct 6 feet high wall along the boundaries of the non-forest land proposed for CA.
3.2	User Agency shall provide at its cost required number of Solar Pumps as given by the forest Department for irrigating the CA plantaion.

After receipt of compliance report on fulfillment of all of the above conditions from the State Government, proposal will be considered for final approval under section '2' of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980. The User Agency shall take up the work as per the guidelines in force and after ensuring that all necessary clearances for the entire stretch are in place. Working permission, if any issued, shall be intimated to RO, Gandhinagar. Transfer of forest land shall not be affected till final approval is granted by the Central Government in this regard. Further, it may also be noted that this **In-principle/stage-I** approval shall be valid for a period of 2 years from the date of issue of this letter. In the event of non-compliance of the above conditions, this In-principle approval shall be revoked after two (02) years

Your's faithfully

(Shrawan Kumar Verma)
Regional Officer/Head of Department
Regional Office, Gandhinagar
MoEF&CC, Govt. of India

DIPR/C/10606/2025

भव्य कावड़ यात्रा आज चेक बाउंस के मामले में कांग्रेस के पूर्व पार्षद को जेल भेजा

छबड़ा (निर्स)। श्रावण मास के चौथे सोमवार को भव्य कावड़ यात्रा निकाली जाएगी। शिवभक्त कस्बे से सात किलोमीटर दूर गूगोर गांव के समीप प्रवाहित हो रही पार्वती नदी के तट पर पहुंचेगे और बाबा का जलाभिषेक किया जाएगा। कावड़ यात्रा का जगह-जगह स्वागत द्वार, पुष्पवर्षा के साथ स्वागत किया जाएगा। नागेश्वर मंदिर सेवा समिति के अध्यक्ष गणेश भार्गव के अनुसार आज

कस्बे में कावड़ यात्रा निकाली जाएगी। दूर गूगोर गांव के समीप प्रवाहित हो रही पार्वती नदी के तट पर पहुंचेगे और यहां पूजा-अर्चना व महाआरती के बाद शिव भक्त पार्वती नदी में से अपने-अपने पात्रों मे जल को भरकर वहां से पैदल-पैदल भव्य शोभायात्रा के साथ शुरू होंगे।

कोटा, (निर्स)। बोरखेड़ा पुलिस टीम ने चेक बाउंस के पुराने मामले में फरार चल रहे कांग्रेस के पूर्व पार्षद आनंद पाटनी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से पूर्व पार्षद को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। बोरखेड़ा थानाधिकारी देवेश भारद्वाज ने बताया कि पूर्व पार्षद आनंद पाटनी के खिलाफ साल 2015 में एक चेक बाउंस का मामला था। आरोपी के खिलाफ न्यायालय से स्टैंडिंग वारंट प्राप्त हुआ था। पूर्व पार्षद आनंद पाटनी मामले में लम्बे समय से फरार चल रहा था, फरारी काट रहे आरोपी आनंद पाटनी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया।

कोटा, (निर्स)। कैट वीमेन विंग जिला कोटा द्वारा आयोजित नन्हे बालक-बालिकाओं के लिये तलवंडी स्थित जाट समाज में लिटिल स्टार आईकॉन प्रतियोगिता में सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया। कैट वीमेन विंग की अध्यक्ष नीलम विजय ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विजेता व उपविजेता बालक-बालिकाओं को प्रोत्साहित करते हुये पुरस्कृत किया।

नी.पी.सारस्वत ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। कुलगुरु प्रोफेसर बी.पी.सारस्वत ने कहा कि आज महिलायें व बच्चें किछी पार्टी व क्लब की ओर आकर्षित हो रहे हैं वहीं आज राजस्थान की रंग में पेश किया है जिसमे छोटे बच्चे रंग-बिरंगी लहरियों में सजे-धजे राजस्थानी लोकगीतों पर केटवाँक करते हुये अद्भुत लग रहे है। घूमर नृत्य की लय और लोकधुनों की गूँज ने महोत्सव के राजस्थान की खूबसूरती व संस्कृति से भर दिया है। लोकसभा स्पीकर बिरला ने कोटा साड़ी व लहरिया को देशव्यापी व वैश्विक स्तर पर अतुड़ी पहचान को बताया। बिरला के साथ नन्हे बच्चे ने सेल्फी व फोटो लेने का उत्साह रखा। कैट वीमेन टीम ने ओम बिरला को लहरिया के रंग में रंगे साफे को पहनाकर व दुपट्टा पहना कर अभिनंदन करने के लिए इस तरह के आयोजनों की आवश्यकता पर भी बल दिया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों में कैट के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष मनोज गोयल संभागीय महिला अध्यक्ष सुमन गोयल, प्रदेश सचिव

हरियाली,बारिश और उमंग के प्रतीक लहरिया थीम पर लिटिल स्टार आईकन बने बच्चे

कोटा, (निर्स)। कैट वीमेन विंग जिला कोटा द्वारा आयोजित नन्हे बालक-बालिकाओं के लिये तलवंडी स्थित जाट समाज में लिटिल स्टार आईकॉन प्रतियोगिता में सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया। कैट वीमेन विंग की अध्यक्ष नीलम विजय ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विजेता व उपविजेता बालक-बालिकाओं को प्रोत्साहित करते हुये पुरस्कृत किया।

■ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लहरिया को बताया राजस्थान की वैश्विक पहचान, विजेताओं को पुरस्कृत किया



लिटिल स्टार आईकॉन प्रतियोगिता में सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया।

बी.पी.सारस्वत ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। कुलगुरु प्रोफेसर बी.पी.सारस्वत ने कहा कि आज महिलायें व बच्चें किछी पार्टी व क्लब की ओर आकर्षित हो रहे हैं वहीं आज राजस्थान की रंग में पेश किया है जिसमे छोटे बच्चे रंग-बिरंगी लहरियों में सजे-धजे राजस्थानी लोकगीतों पर केटवाँक करते हुये अद्भुत लग रहे है। घूमर नृत्य की लय और लोकधुनों की गूँज ने महोत्सव के राजस्थान की खूबसूरती व संस्कृति से भर दिया है। लोकसभा स्पीकर बिरला ने कोटा साड़ी व लहरिया को देशव्यापी व वैश्विक स्तर पर अतुड़ी पहचान को बताया। बिरला के साथ नन्हे बच्चे ने सेल्फी व फोटो लेने का उत्साह रखा। कैट वीमेन टीम ने ओम बिरला को लहरिया के रंग में रंगे साफे को पहनाकर व दुपट्टा पहना कर अभिनंदन करने के लिए इस तरह के आयोजनों की आवश्यकता पर भी बल दिया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों में कैट के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष मनोज गोयल संभागीय महिला अध्यक्ष सुमन गोयल, प्रदेश सचिव

अशोक माहेश्वरी, कोटा जिलाध्यक्ष अनिल मुंदड़ा, डॉ.सपना अग्रवाल कांग्रेस महिला प्रदेश उपाध्यक्ष प्रियंका नंदवाना, समाजसेवी तुपित नागर, पार्षद योगेश आहलूवालिया, डॉ.रसीला भूरिया व खुशी शर्मा तथा टीम नक्षत्र के सदस्य रिचा विजय कीर्ति खडेलवाल प्रीति जैन स्मिता पाटनी ने शिरकत कर प्रोत्साहित किया। विजेताओं को विजेता व उपविजेता निर्णायक मंडल सुनिता जैन व दिव्या जैन रही। कार्यक्रम की उद्घोषिका अंकिता खडेलवाल व शुभि गुप्ता ने राजस्थानी अंदाज में की। अध्यक्ष नीलम विजय, सचिव भविका प्रीत रमानी कार्यकारी अध्यक्ष रिचा गुप्ता उपाध्यक्ष रक्षा नरूका कोषाध्यक्ष डॉ. रुचि जौहरी मीडिया को ऑरिडिनेटर कीर्ति मितल जैन, प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स-चित्रांगी अग्रवाल, मधु विजय, आकांशा गुप्ता, नंदिनी श्रृंगी, अंकिता विजय, शुभी गुप्ता, नेहा प्रकाश, रीना विजय व सिया आडवाणी ने कार्यक्रम की सफलता में सहयोग किया।

‘प्राकृतिक सौंदर्य और आस्था का संगम है नागेश्वर मंदिर’



नागेश्वर मंदिर कस्बे की पहाड़ी पर स्थित है।

छबड़ा (निर्स)। यहां की पहाड़ी पर स्थित नागेश्वर मंदिर एक ऐसा धार्मिक स्थल है, जहाँ प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। हरियाली की अनूपम छटा से घिरी इस स्थल की खूबसूरती न केवल आँखों को सुकून देती है, बल्कि मन को भी शांति और आनंद से भर देती है। यह धार्मिक स्थल आध्यात्मिक और प्राकृतिक पर्यटन के लिए विशेष पहचान रखता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु नागेश्वर बाबा का आशीर्वाद लेने के साथ ही इस स्थान की प्राकृतिक सुंदरता का भरपूर आनंद उठाते हैं। वर्षभर यहाँ श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रहती है, किंतु सावन में यह धार्मिक स्थल विशेष रूप से भक्तिमय वातावरण से भर जाता है, जब हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर समिति से जुड़े लोग बताते हैं कि 22 अगस्त 1985 में नींव खुदाई के दौरान नागेश्वर बाबा की प्रतिमा का प्राकट्य हुआ था। पुरातत्व विभाग के कर्मचारी द्वारा प्रतिमा का परीक्षण कर यह प्रतिमा 2500 वर्ष पुरानी बताई गई है। प्रतिमा की प्राण-प्रतिष्ठा 7 मार्च 1991 को हुई थी। इसके बाद से ही यहां नागेश्वर बाबा भक्तों के दुःख, संकटो का निवारण कर रहे हैं। श्रद्धालुओं को 148 सीढ़ियां चढ़ना पड़ता है। उसके उपरांत ही नागेश्वर बाबा के दर्शन होते हैं। प्राचीन शिवलिंग होने के कारण राजस्थान सहित मध्यप्रदेश के लोग भी यहां बड़ी संख्या में दर्शन करने आते हैं। इसी के साथ ही मां दुर्गा व हनुमानजी भक्तों के संकट हरते हैं। नगरपालिका की ओर से प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि पर्व पर यहां पांच दिवसीय मेला आयोजित किया जाता है। जिसमें रंगमंच पर प्रतिदिन कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाती हैं। मेले में कस्बे सहित ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी बड़ी संख्या में आते हैं। नागेश्वर सेवा समिति की ओर से महाशिवरात्रि की पूर्व संख्या पर संगीतमय रात्रि जागरण कर दूसरे दिन नागेश्वर बाबा का मनमोहक श्रृंगार किया जाता है।

कार चोर गिरोह का पर्दाफाश, तीन आरोपी गिरफ्तार 1 2 कारें व एक कार का इंजन जब्त

कोटा, (निर्स)। रेलवे कॉलोनी पुलिस टीम ने कार चोरी की दर्ज रिपोर्ट पर बड़ी कार्यवाही करते हुए कार चोर गिरोह का पर्दाफाश किया और मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे चोरी की गई 12 कारों सहित एक कार का इंजन बरामद किया है। पकड़े गये बदमाशों ने अलग-अलग क्षेत्रों से ईंको कारों का अपना निशाना बनाया। पकड़े गये गिरोह के सदस्य पिछले लम्बे समय से कारें चोरी करते हुए आ रहे थे। शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वी गोतम ने बताया कि 30 जुलाई को परिव्रादी

■ कारों को मोडिफाई करके बेचते थे



कोटा में कार चोर गिरोह के तीन आरोपियों को रेलवे कॉलोनी पुलिस टीम ने चोरी की गई कारों सहित गिरफ्तार किया।

किया जिससे पृष्ठताछ पर वक्फ नगर दादाबाड़ी निवासी आदिल (29) और छत्रपुरा तालाब विज्ञान नगर निवासी मोहम्मद हुसैन उर्फ बबलू (34) को गिरफ्तार किया गया। शहर एसपी ने बताया कि पकड़े गये बदमाशों ने पृष्ठताछ के दौरान थाना रेलवे कॉलोनी के साथ-साथ दादाबाड़ी, विज्ञान नगर बोरखेड़ा, कैथूनीपोल और कोटा ग्रामीण के सुल्तानपुर से चोरी करने की गई पांच कारो के इंजन नम्बर, चैचिस नम्बर और बॉडी मोडिफाई कर दी। उन पांच सदिय कारों को भी डिटेन किया गया। पकड़े गये आरोपियों से अनुसंधान जारी है। तरीका वारदात:-शहर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी सैययद औसाफ अली उर्फ शानु सूर्य नगर का निवासी है। शहर एसपी ने बताया कि मामले में सामने आया कि सैययद औसाफ अली जो सुल्तानपुर में अपनी मौसी के पास रहने के दौरान उस पर कर्जा हो गया और उसके बाद वह कोटा मे रहने लगा और कर्जा अधिक होने और कोई काम नहीं मिलने पर आरोपी ने 2023 में विज्ञान नगर इलाके से एक कार चुराई और विज्ञान नगर निवासी मोहम्मद हुसैन उर्फ बल्लू को बेच दी, पकड़ा गये आरोपी बल्लू का विज्ञान नगर में ही कार वाशिंग व कार रिपेयरिंग का काम है। ममाले में सामने आया कि आरोपी सैययद औसाफ अली उर्फ शानु, मोहम्मद हुसैन उर्फ बल्लू और आदिल ने तीनों ने मिलकर जल्दी अमरी बनने व शोक को पूरा करने के लिये कारें चोरी की योजनाएं बनाई और ईंको कार को डिमांड ज्यादा होने से रात्रि के समय सुनसान स्थानों पर खड़ी ईंको कारों को निशाना बनाते थे, और देशी तकनीकी से शानु कारों के लॉक तोड़कर कारों को चुराता था और आदिल, बल्लू को संभला देता था। तीनों आरोपी चोरी हुई कारो के इंजन नम्बर, चैचिस नम्बर बदलकर पुराने कबाड़े की कारों व दुर्घटनाग्रस्त कारों के इंजन नम्बर व चैचिस नम्बर चुराई कारो में लगा देते थे।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को नई दिल्ली के जोधपुर हाउस में “एक पेड़ मां के नाम” अभियान के तहत बिल्व का पौधा लगाया। इस अवसर पर उन्होंने कहा जैव विविधता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाने चाहिए।

मुख्यमंत्री भजनलाल ने जोधपुर हाउस में बिल्व का पौधा लगाया

दिल्ली में पत्रकारों से वार्ता में उन्होंने रिफाइनरी के काम में तेजी लाने की बात कही

नई दिल्ली/जयपुर, 3 अगस्त। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को नई दिल्ली के जोधपुर हाउस में ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत बिल्व का पौधरोपण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बिल्व जैसे पौधे धार्मिक और औषधीय दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। जैव विविधता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाने चाहिए।

शर्मा ने रविवार को नई दिल्ली के

■ **मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में धार्मिक पर्यटन तथा विरासत से जुड़े पर्यटन स्थलों को बढ़ावा दिया जायेगा। प्राचीन हवेलियों और हेरिटेज सम्पत्तियों की सूची बनवाई गई है तथा उनके उचित रखरखाव के लिए सरकार हर संभव सहयोग करेगी।**

बीकानेर हाउस में पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि हमारी सरकार राजस्थान के चर्हुमुखी विकास के लिए कार्य कर रही है। राजस्थान रिफाइनरी

के काम में तीव्रता लाकर यहां बनने वाले बाय-प्रोडक्ट्स को संसाधित करके इससे जुड़े उद्योगों की स्थापना पर केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम

किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि प्रदेश में विभिन्न प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें विशेष रूप से धार्मिक अब पेरलीक का मामला जयपुर ट्रांसफर होने के बाद जब्त कैश और अन्य माल ईडी कोर्ट को भेज दिया गया।

श्रीनगर हवाई अड्डे पर सेना के अधिकारी व एयरलाइन कर्मचारियों में मारपीट

स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि एक कर्मचारी की रीढ़ की हड्डी टूट गई

श्रीनगर, 3 अगस्त। श्रीनगर में हवाई अड्डे पर सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा एक निजी एयरलाईंस के चार कर्मचारियों को कथित तौर पर बुरी तरह पीटने की घटना के प्रकाश में आने के बाद एयरलाईंस ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को पत्र लिखकर मामले में उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

एयरलाईंस स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने बताया कि कश्मीर में तैनात एक वरिष्ठ सेना अधिकारी ने 26 जुलाई को श्रीनगर हवाई अड्डे पर उसके चार कर्मचारियों पर कथित तौर पर तब हमला बोल दिया जब उन्होंने सामान के किराए के भुगतान का अनुरोध किया। इस मामले की प्राथमिकी थाने में दर्ज

■ **एयर लाइन्स के अनुसार, सेना अधिकारी के सामान का वजन अधिक था तथा उनसे बोर्डिंग गेट पर अतिरिक्त भार के भुगतान के लिए कहा गया था।**

■ **सेना ने कहा कि वह जाँच में पूरा सहयोग करेगी।**

कराई है और नागरिक उड्डयन नियमों के अनुसार यात्री का नाम काली सूची (नो-फ्लाई) में डालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

एयरलाईंस ने कहा कि उसने घटना का सीसीटीवी फुटेज हासिल करके पुलिस को सौंप दिया है और वह इस मामले की पूरी कानूनी और नियामकीय जाँच पर जोर देगी।

प्रवक्ता ने बताया कि उक्त अधिकारी ने श्रीनगर से दिल्ली जाने वाली उड़ान संख्या एसजी -386 के बोर्डिंग गेट पर तैनात एयरलाईंस के

चार कर्मचारियों को इतना पीटा कि एक कर्मचारी की रीढ़ की हड्डी टूट गई और उसके जबड़े में गंभीर चोट आई। जब दूसरे कर्मचारी उसे बचाने आए तो अधिकारी ने उन्हें भी पीटा।

प्रवक्ता ने कहा कि अधिकारी के सामान का वजन 10 किलोग्राम था जबकि, मुसाफिरों की विमान के अंदर केवल सात किलोग्राम ले जाने की इजाजत है।

प्रवक्ता ने कहा, "जब उनको विनम्रतापूर्वक इस बारे में बताया गया और लागू शुल्क का भुगतान के

लिए कहा गया, तो यात्री ने इन्कार कर दिया और बोर्डिंग प्रक्रिया पूरी किए बिना ही जबरन एयरोब्रिज में प्रवेश कर गया। यह विमानन सुरक्षा प्रोटोकॉल का स्पष्ट उल्लंघन था।"

प्रवक्ता ने कहा, "सीआईएसएफ के एक अधिकारी ने उसे वापस गेट तक पहुँचाया।" इस मामले में सेना ने कहा है कि वह जांच में पूरा सहयोग करेगी। सेना ने बयान में कहा, हम अनुशासन के उच्च मानकों पर चलते हैं और इस घटना को गंभीरता से ले रहे हैं।

बद्रीनाथ हाईवे पर पुल क्षतिग्रस्त, भारी वाहनों पर रोक

चमोली, 03 अगस्त। उत्तराखण्ड के चमोली जिले मे शनिवार रात्रि को भारी वर्षा होने के कारण बदरीनाथ हाईवे पर हनुमान चट्टी स्थित मोटर पुल के दोनों ओर की एबटमेंट सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त हो गयी है। सतकंता और सुरक्षा को देखते हुए फिलहाल भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगाई गई

■ **हल्के वाहनों का आवागमन चालू रखा गया है तथा बद्रीनाथ यात्री भी फिलहाल जारी है।**

है। छोटे वाहनों टैक्सी, कार सहित अन्य हल्के वाहनों के आवागमन पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। बदरीनाथ यात्रा फिलहाल जारी है।

पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने जानकारी देते हुए रविवार को बताया फिलहाल बदरीनाथ हाईवे यहाँ पर हल्के वाहनों के ही खोला गया है। पांडुकेनवर से ऊपर सभी भारी वाहनों को प्रतिबंधित किया गया है।

गडकरी के घर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) पुलिस और डॉंग स्कॉयड की टीम ने गडकरी के घर मेंसर्व ऑपरेशन भी चलाया।

कुछ घंटों बाद गडकरी के घर को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम उमेश विष्णु राउत है। उमेश विष्णु राउत मेडिकल चौक स्थित एक देसी शराब की दुकान पर काम करता है। पुलिस ने उसे नागपुर के बीमा दवाखाना के पास से गिरफ्तार किया है।

बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नागपुर में ही मौजूद हैं। पुलिस की टीम अब गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर धमकी देने के पीछे की संशा को जानना चाहेगी कि कहीं इस घटना में कोई और एंगल तो नहीं है।

सरकार ने 35 ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) अधिक वसूली गई राशि को वसूलना शामिल होगा। एनपीपीए ने साफ किया है कि निर्धारित मूल्यों में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) शामिल नहीं है, जिसे लागू होने पर जोड़ा जा सकता है।

निर्माताओं को सभी वैधानिक आवश्यकताओं का पालन करना होगा, इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से फॉर्म वी में अपडेटेड प्राइस लिस्ट जारी करनी होगी और एनपीपीए तथा राज्य औषधि नियंत्रकों को जानकारी देनी होगी। स्पेसिफाइड फॉर्मूलेशन और निर्माताओं के लिए जारी किए गए किसी भी पूर्व मूल्य आदेश को इस लेटेस्ट नोटिफिकेशन द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को भूपेश बघेल की अग्रिम जमानत पर सुनवाई की संभावना

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री ने आशंका जताई है कि राजनीतिक प्रतिशोध के तहत उनकी गिरफ्तारी की जा सकती है

रायपुर, 03 अगस्त। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तथा पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल को आशंका है कि उन्हें शराब,कोयला और महादेव सट्टा एप घोटालों में नाम आने के बाद कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है।

इस गिरफ्तारी से बचने के लिए बघेल ने सर्वोच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका लगाई है और न्यायालय सोमवार को उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए विचार कर सकता है।

बघेल ने याचिका में मांग की है कि उन्हें इन मामलों में किसी भी तरह से गिरफ्तार न किया जाए और जांच में सहयोग करने का अवसर दिया जाए। याचिका में यह भी उल्लेख किया है कि जिस तरह उनके बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी राजनीतिक द्रष्टे के चलते की गई, उसी तरह उन्हें भी निशाना बनाया जा सकता है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने आशंका जताई है

■ **शराब, कोयला तथा महादेव सट्टा घोटाले में सीबीआई और ईडी की जाँच के बाद उनके पुत्र चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हो चुकी है। राज्य व केन्द्र की जाँच एजेंसियों ने कुछ समय पूर्व संबंधित मामलों की जाँच की गति तेज कर दी है।**

कि, राजनीतिक प्रतिशोध के तहत उनकी गिरफ्तारी की जा सकती है। यह याचिका ऐसे समय में दाखिल की गई है जब राज्य और केन्द्र की जांच एजेंसियों, ईडी तथा आर्थिक अपराध शाखा सहित कई केन्द्रीय जांच एजेंसियों ने संबंधित मामलों की जांच तेज कर दी है।

यह याचिका सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए लिस्टिंग की गई है। इसके अलावा बघेल और उनके बेटे ने सीबीआई और ईडी द्वारा की जा रही जांचों की वैधता को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। याचिका में सवाल उठाया गया है कि सीबीआई और ईडी

को छत्तीसगढ़ में जांच करने का अधिकार किस आधार पर मिला, जब राज्य सरकार ने पहले ही उनकी आम सहमति वापस ले ली थी।

सितंबर से ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) 12 के अनुसार हर साल रजिस्टर्ड पोस्ट की संख्या में गिरावट आ रही है। साल 2011-12 में रजिस्टर्ड डाक से भेजने वाले आर्टिकल 24 करोड़ से घटकर 2019-20 में 18 करोड़ के रह गए। 25 फीसदी की कमी साफ देखी जा सकती है। कोरोना के बाद से तो स्थिति और खराब हो गई है।

सरयू नहर में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) आया। बमुश्किल खिड़की का शीशा तोड़कर एक-एक की बाहर निकाला। तब तक सभी की मौत हो चुकी थी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना का संज्ञान लेकर शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। सीएम ने मृतकों के परिजनों को पांच लाख की आर्थिक सहायता दिए जाने के निर्देश दिए हैं।

चुनाव आयोग ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) पत्र नहीं रख सकता है। अगर रखता है तो यह अपराध है। एनडीए के प्रवक्ताओं ने साफ कहा कि चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और तत्काल इस मामले को लेकर तेजस्वी यादव पर मुकदमा दायर करना चाहिए।

‘साढ़े छः ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) आयोग के कथित कदम का विरोध करते हुए आरोप लगाया था कि यह भाजपा की उन रज्यों की वोट देने वाली आबादी का डेटा बदलने की चाल है जहाँ उसकी कोई पकड़ नहीं है।

प्रेनाइट खदान ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबु नायडू ने इस दुर्घटना पर गहरा दुःख व्यक्त करते हुए अधिकारियों को घायल श्रमिकों को बेहतर चिकित्सा प्रदान करने के निर्देश दिये हैं।

एयर इंडिया का पुनः “राष्ट्रीयकरण” ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) विमान ऑर्डर दिया है, तकनीक और कर्मचारियों के प्रशिक्षण में निवेश किया है, और ब्रांड की साख वापस लाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह का बदलाव, अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार भी, कई सालों में होता है, महीनों में नहीं।

आज जो समस्याएँ एयर इंडिया में देखी जा रही हैं, वे पुनर्गठन की प्रक्रिया का हिस्सा हैं, न कि व्यवस्था की विफलता। अभी अगर फिर से इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, तो भारत के आर्थिक सुधारों की साख को बड़ा झटका लगेगा और वैश्विक निवेशकों का भरोसा कमजोर होगा, जिन्हें नीति में स्थिरता चाहिए।

यह बात सही है कि एयर इंडिया के साथ भावनात्मक लगाव आज भी बना हुआ है। दशकों तक यह भारत की हवाई

■ **पर, यह भी जरूरी है कि एयर इंडिया का मैनेजमेंट अपनी दिक्कतों व कमियों के बारे में सही जानकारी दे जनता को, नहीं तो यह “इम्पेशन” जोर पकड़ लेगा कि मैनेजमेंट के पास सिविल एविएशन का पूरा अनुभव नहीं है और कार्य कुशलता के अभाव में कंपनी डूब जायेगी।**

पहचान रहे हैं, प्रधानमंत्रियों को ले जाने वाली, संकट में नागरिकों को वापस लाने वाली और प्रवासी भारतीयों को देश से जोड़ने वाली एयरलाइन। जब वही एयरलाइन निजी हाथों में संघर्ष करती दिखती है, तो लोगों को पीड़ा होती है।

अगर टाटा समूह द्वारा दी जा रही पूंजी और स्वतंत्रता के बावजूद एयरलाइन लगातार विफल होती है, तो सार्वजनिक हित की बात फिर से उठ सकती है। मनीष तिवारी की यह चिंता, कि गैर-विमानन पेशेवर (नॉन

एविएशन प्रॉफेशनल्स) से चला रहे है, इस बड़े भय के दर्शाती है कि एयर इंडिया की आत्मा सिर्फ लाभ कमाने के चक्कर में कहीं खो रही है।

इसके अलावा, भारत जैसे विशाल देश में हवाई संपर्क एक रणनीतिक संसाधन है। अगर निजी नियंत्रण में कुछ प्रमुख मार्ग घाटे का सौदा बनते हैं, तो जनता की जरूरतें पूरी नहीं होंगी। ऐसे में सरकार को सीधे या रैग्युलेशन के जरिए हस्तक्षेप करना पड़ सकता है।

फिर भी, एयर इंडिया का पुनः राष्ट्रीयकरण अभी जल्दबाजी होगी और

मुश्किल से हो रहे सुधारों को कमजोर कर दिया का खतरा पैदा हो सकता है। एयर इंडिया को कब्जे में लेने की नहीं, बल्कि कड़ी गिरानी की जरूरत है। सरकार को अपने नियामक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए सेवा गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रतिस्पर्धा पर नजर रखनी चाहिए। वहीं, टाटा समूह को संवाद बेहतर करना होगा, तेजी से कदम उठाने होंगे और यात्रियों व नीति-निर्माताओं, दोनों को यह भरोसा दिलाना होगा कि वे इस जिम्मेदारी के लायक हैं।

निजीकरण कभी कोई जादू की छड़ी नहीं था। यह एक ऐसा कदम था, जिससे सरकार को एयरलाइन चलाने के काम से आज़ाद किया जा सके, ताकि वह शासन पर ध्यान दे सके। इसी भावना में, जरूरी है कि जो टूटा है, उसे ठीक किया जाए, बिना उसे फिर से पूरी तरह बिगाड़े।